सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 269, नई दिल्ली । रविवार, 08 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण दिल्लीवालें परेशान है

06 बढ़ता मृदा प्रदूषण, घटता उत्पादन

08 बढ़ता मृदा प्रदूषण, घटता उत्पादन

क्या दिल्ली की जनता जानती हैं की परिवहन विभाग की जनहित में कितनी क्षेत्रीय शाखाएँ राजपत्र अधिसूचना के अनुसार आज भी कार्यरत हैं ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में राजपत्र अधिसूचना के अनुसार आज की तारीख़ में

1. 13 क्षेत्रीय शाखा निजी वाहनों के प्रति
2. मुख्यालय शाखा व्यवसायिक गतिविधि वाहनों के प्रति
3. आटो शाखा व्यवसायिक गतिविधि तीन पहिया वाहनों के प्रति
4. टैक्सी शाखा व्यवसायिक गतिविधि चार पहिया गुड्स एवम्-12 सवारी तक के वाहनों के प्रति
5. राज्य परिवहन प्राधिकरण शाखा व्यवसायिक गतिविधि में शामिल वाहनों के प्रति

इनके अलावा राजपत्र अधिसूचना के अनुसार व्यवसायिक गतिविधि में शामिल वाहनों की जांच प्रमाण पत्र जारी करने के लिए

1. बुराड़ी वाहन जांच शाखा
2. बुराड़ी आटो वाहन जांच शाखा
3. झूलझूली वाहन जांच शाखा

तीन वाहन जांच शाखाएं उपलब्ध एवम् कार्यरत हैं।

13 शाखाएं निजी वाहनों के प्रति और 4 शाखाएं व्यवसायिक गतिविधि में शामिल वाहनों के प्रति एवम्-3 शाखाएं

वाहन जांच प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उपलब्ध एवम्-कार्यरत है।

अब आप को बताते हैं राजपत्र अधिसूचना के अनुसार जनहित में चालित निजी वाहनों के प्रति 13 शाखाओं में से परिवहन आयुक्त द्वारा निजी आदेश जारी कर न्यायिक अवहेलना करते हुए जमीनी स्तर पर मात्र 4 शाखाओं को चालित किया हुआ है। और अन्य 9 राजपत्र अधिसूचना के अनुसार चालित निजी वाहनों की शाखाओं के कार्यों को इन चार शाखाओं मे विलय कर दिया।

3 वाहन जांच शाखाओं में से जमीनी स्तर पर अभी 2 वाहन जांच शाखा कार्यरत हैं और 1 वाहन जांच शाखा को भी विलय कर दिया।

इसके अतिरिक्त आपकी जानकारी हेतु बता दें इन सभी शाखाओं में तकनीकी अधिकारी जिन्हें विशेष रूप से इन शाखाओं में कार्य को करने के लिए अर्ध- न्यायिक शक्ति (Quasi Judicial Power) प्रदान है ही कार्यरत हो सकते हैं।

परिवहन आयुक्त ने अपनी निजी हठ के अंतर्गत 13 + 5 + 3 = 21 शाखाओं की जगह जमीनी स्तर पर मात्र 4 + 5 +2 = 11 शाखाएं ही चालित रखी हुई है और इन 11 चालित शाखाओं में नियमानुसार कार्य करने वाले अधिकारियों की गिनती मात्र 2 है बाकी 9 शाखाओं पर अपने निजी इच्छा के अनुसार उन अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त कर रखा है जो नियमानुसार, एवम्-सुप्रीम कोर्ट, कैट एवम्-दिल्ली विधि मंत्रालय सचिव के अनुसार मान्य नहीं है।

परिवहन आयुक्त द्वारा गैर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी आदेश को पालन करवाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनहित में राजपत्र अधिसूचना द्वारा शुरू शाखाओं को बंद कर लागू करने और गैर तकनीकी अधिकारियों को तकनीकी पदों पर नियुक्त करने की जानकारी दिल्ली सरकार, मुख्य सचिव और उपराज्यपाल को है।

अब आप स्वयं फैसला करे जो प्रशासनिक अधिकारी जनित के लिए पद पर कार्यरत हो और सिर्फ अपने पद की शक्ति का प्रयोग जनहित की जगह जन अहित में कर रहा हो तो उस राज्य की जनता खास तौर से महिलाएं वाहनों में कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती हैं और कैसे सुखद अनुभव प्राप्त कर सकती हैं चाहे जनहित में कितने भी आदेश न्यायिक प्रणाली, भारत देश का संविधान और भारत सरकार या राज्य सरकार घोषित कर दे।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

फरवरी 2026 तक सड़कों पर नहीं दिखेंगी पुरानी बसें, ई-बसों का बढ़ेगा बेड़ा; सीएनजी गाड़ियां भी हटेंगी

दिल्ली की सड़कों से परिवहन निगम ने अपनी पुरानी बसों को फरवरी 2026 तक पूरी तरह से हटाने की योजना तैयार की है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से बसों को हटाया जाएगा। जैसे-जैसे पुरानी बसे हटेंगी उसकी जगह पर नई इलेक्ट्रिक बसें को लाया जाएगा।

नई दिल्ली। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डीटीसी और क्लस्टर सेवाओं में पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ई-बसों के बेड़े का विस्तार किया जा रहा है। फिलहाल, डीटीसी 1,602 ई-बसों का संचालन कर रही है, वही क्लस्टर बेड़े में 400 ई-बसें हैं। इसे और मजबूत करने के लिए, आने वाले दिनों में 1,038 नौ-मीटर ई-बसें और 200 12 मीटर ई-बसें शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त, क्लस्टर सेवा में 1,040 नौ-मीटर ई-बसें और 1,600 12 मीटर की ई-बसें जल्द आएंगी।

दो हफ्ते में 150 मोहल्ला बसों का शुरू होगा संचालन

अधिकारियों के अनुसार, मोहल्ला बसों के संचालन के लिए रूट तय कर लिए गए हैं। 150 से अधिक बसों की खेप आ चुकी है। मौजूदा समय में चार से पांच रूटों पर बसों का ट्रायल किया जा रहा है। आगामी दो सप्ताह के भीतर 150 मोहल्ला बसों को संचालन शुरू होगा। सरकार का दावा है कि दिल्ली में 2025 तक 10,480 बसों में से 80 फीसदी बसें इलेक्ट्रिक हो। इस लक्ष्य को पूरा करने से दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा वाला शहर बन जाएगा। अभी दिल्ली में 1970 इलेक्ट्रिक

बसें हैं। यह बसें साल 2022 में 249, 2023 में 1050 और 2024 में 670 शामिल की गई हैं।

14 माह में 2,624 सीएनजी बसें हटेंगी

अधिकारियों ने बताया कि पुरानी बसों को हटाने के क्रम फरवरी 2026 तक चलेगा। अगले 14 माह में 2,624 सीएनजी बसों को सड़कों से हटाया जाएगा। इस माह 188 बसें हटाई जाएंगी। मार्च 2025 अंत तक कुल 950 हटाई जाएंगी। साल 2025 अंत तक दो हजार से अधिक बसों को हटाया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में 2,760 सीएनजी बसें ऐसी हैं जो अपनी उम्र सीमा पार कर चुकी हैं। इन बसों की स्थिति और खराब होती जा रही है। ऐसे में चरणबद्ध तरीके से बसों को हटाया जाएगा। बता दें कि डीटीसी के अंतर्गत 67 डिपो और परिवहन विभाग द्वारा प्रबंधित क्लस्टर संचालन के माध्यम से 7,425 बसों का बेड़ा संचालित होता है।

इसमें 5,423 सीएनजी बसें और 2,002 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। डीटीसी 44 डिपो में 4,278 बसों की देखरेख करती है, जिनमें 2,676 सीएनजी बसें और 1,602 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। वहीं दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) 23 डिपो में 3,147 बसों का प्रबंधन करता है, जिनमें 2,747 सीएनजी बसें और 400 इलेक्ट्रिक बसें हैं।

13 महीनों से नौकरी वापिस पाने के लिए सड़कों पर बस मार्शल

परिवहन विशेष न्यूज

क्या दिल्ली सरकार फिर से उन्हें उनकी नौकरी वापिस दे सकती हैं या नहीं ?, जाने कुछ छुपे हुए सवाल

सिविल डिफेंस बस मार्शल अपनी नौकरी वापिस पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और कभी दिल्ली सचिवालय, कभी मुख्यमंत्री निवास, कभी केजरीवाल निवास, कभी जंतर मंतर और कभी भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

क्या वह सच में नौकरी वापिस पाने के हकदार हैं या नहीं ?

इसके लिए कुछ सवालों के जवाब अनिवार्य हैं पर कोई भी इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं या कहे समर्थ है।

आप भी जाने उनमें से कुछ सवाल जिनके जवाबो के बिना इतनी बड़ी संख्या के दिल्ली वासियों को न्याय मिलना मुश्किल है । अगर आप में से किसी के पास निम्न सवालों के सबूतों के साथ जवाब उपलब्ध हो तो अवश्य हमें भेजे।।

अब जाने सवाल

1. किस नियम/ कानून और आधार पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन्हें नियुक्ति दी थी ?

2. किस कारण स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन्हें उनके कार्यों से मुक्त करने की उपराज्यपाल दिल्ली को सिफारिश की थी ?

3. किस आधार पर दिल्ली के यह सिविल डिफेंस बस मार्शल अपनी नौकरी वापिस पाने के लिए लगातार उसी दिन से प्रयास कर रहे हैं ?

दिनांक 7 दिसंबर 2024 को बस मार्शलों ने बीजेपी कार्यालय आईटीओ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपने रोजगार के लिए प्रदर्शन किया। बस मार्शलों का कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रदूषण में जो चार महीने की ड्यूटी का लोभ देकर हमारी एकता तोड़ने का कृत्य किया था अब उन बस मार्शलों को जो ड्यूटी कर रहे थे उनको भी हटा दिया गया है और सरकार हमारे साथ षड्यंत्र रच रही है। पिछले 13 महीने से हम अपने रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही। हमारी संख्या 10792 है और हमें बस मार्शलो का रोजगार नहीं वापिस दिया तो हम गली-गली मोहल्ले में किसी भी पार्टी के नेता को नहीं घुसने देंगे।

आग के प्रदर्शन में उनका सीधा और साफ कहना है की अगर हम **बस मार्शल को रोजगार नहीं तो दिल्ली में वोट नहीं।**

रिठाला से कुंडली तक मेट्रो मंजूर, विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली को सौगात

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली से हरियाणा आने-जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। रिठाला से कुंडली तक मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में इस पर मुहर लगी। ये मेट्रो के फेज-4 का छठा कॉरिडोर है। जानिए इस रूट से जुड़ी हर डिटेल।

नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहरी दिल्ली के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। मेट्रो के लिए यहां के लोगों का करीब दो दशक लंबा इंतजार आखिरकार शुक्रवार को खत्म हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के रिठाला-बवाना-नरेला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी। कुल 26.463 किमी लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण मेट्रो के निर्माणाधीन फेज-4 के तहत ही किया जाएगा।

इस कॉरिडोर का 23.737 किमी लंबा हिस्सा दिल्ली में होगा, जिस पर 19 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और केवल 2.726 किमी का हिस्सा हरियाणा में होगा, जिस पर कुंडली और नाथूपुर में दो स्टेशन बनेंगे। इस कॉरिडोर के निर्माण पर करीब 6,230.99 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह 4 साल में बनकर तैयार होगा। डीपीआर के अनुसार इस कॉरिडोर पर प्रतिदिन 1.26 लाख यात्री सफर करेंगे।

कई खूबियां होगी इस कॉरिडोर में

मेट्रो का यह कॉरिडोर अपने आप में कई खूबियों से लैस होगा। यह दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का इकलौता ऐसा सिंगल कॉरिडोर होगा, जो यूपी और हरियाणा, दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। गाजियाबाद के शहीद स्थल/नया बस अड्डा से दिल्ली के रिठाला के बीच वर्तमान में संचालित मेट्रो की रेड लाइन को ही रिठाला से आगे बवाना और नरेला होते हुए हरियाणा के कुंडली और नत्थूपुर तक ले जाया जाएगा। इसके चलते मेट्रो की रेड लाइन की कुल लंबाई भी बढ़कर करीब 60 किमी हो जाएगी और इसके स्टेशनों की संख्या भी बढ़कर 50 हो जाएगी।

हरियाणा से दिल्ली को कनेक्ट करेगा ये कॉरिडोर

यह मेट्रो नेटवर्क का चौथा ऐसा कॉरिडोर होगा, जो हरियाणा और दिल्ली को आपस में कनेक्ट करेगा। अभी मेट्रो की येलो लाइन हरियाणा के ग्रुरुग्राम तक, ग्रीन लाइन बहादुरगढ़ तक और वायलेट लाइन बल्लभगढ़ तक जाती है। इस चौथी लाइन के भी दो स्टेशन कुंडली और नाथूपुर हरियाणा में होंगी, जबकि बाकी के स्टेशन दिल्ली में होंगे। ये पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा। इस पर चलने वाली ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए सनौठ गांव के पास नया डिपो भी बनाया जाएगा।

लाइट मेट्रो चलाने का था प्रस्ताव

रिठाला-कुंडली कॉरिडोर को इसी साल जून में वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने वित्तीय मंजूरी दी थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने भी इसके निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। रिठाला-बवाना-नरेला

कॉरिडोर पहले से ही मेट्रो के फेज-4 का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसे हरियाणा के कुंडली तक एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया। इस कॉरिडोर की लागत कम करने के लिए इस पर लाइट मेट्रो चलाने का भी विचार किया गया, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। बाद में फुल फ्लैज्ड एलिवेटेड लाइन बनाने का ही फैसला किया गया।

इलाके में खाली पड़े हैं सैकड़ों फ्लैट

पिछले एक साल से दिल्ली के उप-राज्यपाल वी. के. सक्सेना भी बाहरी दिल्ली में नए शैक्षणिक और औद्योगिक संस्थान खोलने के लिए विशेष पहल करते आ रहे हैं, ताकि इस इलाके का भी विकास हो सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टविटी का अभाव इस पहल को आगे बढ़ाने में भी रोड़ा बन रहा था। इसी के चलते इस इलाके में डीडीए के सैकड़ों फ्लैट्स भी लंबे समय से खाली पड़े हैं। चूंकि बाहरी दिल्ली में बसों की कनेक्टिविटी भी बहुत कम है, ऐसे में यहां के ग्रामीण इलाकों में रहने और औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले लोग लंबे समय से मेट्रो की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे थे।

दिल्ली-हरियाणा में आना-जाना होगा आसान

शुरुआत में मेट्रो के फेज-1 में ही रिठाला से आगे बरवाला तक मेट्रो ले जाने का प्लान था, लेकिन उस वक्त मध्य दिल्ली में मेट्रो की ज्यादा जरूरत को देखते हुए इसका फंड ब्लू लाइन के एक्सटेंशन में इस्तेमाल कर लिया गया। बाद में कई और मौकों पर भी इस मेट्रो लाइन के निर्माण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया।

हर बार चुनाव के समय खासतौर से बाहरी दिल्ली में मेट्रो के विस्तार की बात उठी, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से मामला टलता रहा। अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस इलाके में भी तेजी से विकास होने की उम्मीद जगेगी। साथ ही बाहरी दिल्ली का राजधानी के अन्य इलाकों से संपर्क भी बढ़ेगा। खासकर कुंडली बॉर्डर के आस-पास रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली और हरियाणा में आना-जाना आसान हो जाएगा।

घर पर आसानी से बनाकर तैयार करें कोल्हापुरी मिसल पाव, यहां देखें रेसिपी

महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में पाव के संग मिसल, भाजी वड़ा, भजिया, आदि कई चीजें मिल जाएंगी। आप भी घर पर कोल्हापुरी मिसल पाव बना सकते हैं। इसलिए आज हम कोल्हापुरी मिसल पाव की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में पाव के संग मिसल, भाजी वड़ा, भजिया, आदि कई चीजें मिल जाएंगी। महाराष्ट्र के वर्कर ने ये स्नैक्स क्लास ने ईजाद किए और फिर धीरे-धीरे ये स्नैक्स देशभर में फेमस हो गए। मिसल पाव, यह ग्रेवी वाला फर्सान होता है जिसे पाव और प्याज वाले सलाद के साथ दिया जाता है। माना जाता है कि साल 1850 में इस व्यंजन का आविष्कार कोंडाजी फरजंद ने किया था। शुरूआत में कोल्हापुर के कुछ स्थानीय भोजनालयों में ही मिसल पाव परोसा जाता था। लेकिन समय के साथ इसने काफी लोकप्रियता हासिल कर ली।

कोल्हापुरी मिसल अपने डार्क कलर और स्पाइसी टेस्ट के लिए भी जाना जाता है। आमतौर पर पाव के बजाय स्लाइल की हुई ब्रेड के साथ परोसा जाता है। पुणे में इसको पोहा के साथ बेस के रूप में बनाया जाता है। वहीं नासिक में मिसल को दही और तले हुए पापड़ के साथ परोसा जाता है। ऐसे में आप भी घर पर आसानी से कोल्हापुरी मिसल पाव बना सकते हैं। इसलिए आज इस आर्टिकल के जरिए कोल्हापुरी मिसल पाव की रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं।

कोल्हापुरी मिसल पाव की सामग्री

अंकुरित मोठ- 1 कप
प्याज- 2 मध्यम
सूखा नारियल- ½
जीरा- 1 बड़ा चम्मच
चक्र फूल- 2
काली मिर्च- 10-12
हरी इलायची- 7-8
इलायची- 1 काली
दालचीनी स्टिक- 1 इंच
सफेद तिल- 1 छोटा चम्मच
धनिया के बीज- 1 बड़ा चम्मच
खसखस- 1 छोटा चम्मच
तेल- 8 बड़े चम्मच
अदरक- 2 इंच मोटा कटा हुआ
लहसुन की कलियां- 12-15
सरसों के बीज- 1 छोटा चम्मच
हरी मिर्च- 2-3
प्याज- 2
स्वादानुसार नमक
करी पत्ते- 8-10
हल्दी पाउडर- 1 छोटा चम्मच
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर- 2 छोटा चम्मच
मिसल मसाला- 2 छोटा चम्मच + 1 बड़ा चम्मच
ताजा धनिया- 2 बड़ा चम्मच कटा हुआ
गार्निश के लिए- तैयार आलू की सब्जी
ताजा कटा हरा धनिया
फरसाण
नींबू के टुकड़े
बारीक कटा प्याज
दही
सफेद ब्रेड के स्लाइस

ऐसे बनाएं कोल्हापुरी मिसल पाव

सबसे पहले मसाला बनाने के लिए कुछ इंग्रीडिएंट्स को भूनकर इसका पेस्ट बना लें। फिर 2 प्याज और नारियल को गैस पर भून लें। जब नारियल काला हो जाए, तो प्याज समेत इसको प्लेट में निकाल लें। अब पैन को गर्म करके उसमें चक्रफूल, धनिया, जीरा, सफेद तिल, काली मिर्च, हरी इलायची और दालचीनी डालकर 1 मिनट तक रोस्ट करें। जब मसाले से खुशबू आने लगे तो इसमें खसखस डालकर कुछ सेकेंड के लिए भूनें और फिर ठंडा कर लें।

अब उसी पैन में थोड़ा सा तेल डालकर गर्मकर लें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें लहसुन और अदरक डालकर ब्राउन होने तक भूनें और सूखे भुने मसालों को ब्लेंडर जार में डालें। फिर इसमें अदरक, प्याज, लहसुन और जला हुआ नारियल डालें। इसमें ½ कप पानी डालकर बारीक पीस लें।

फिर एक पैन में 2 चम्मच तेल डालकर उसमें राई डालकर भूनें, जब राई फूटने लगे तो पैन में हरी मिर्च डालकर 30 सेकेंड तक भूनें। अब पैन में बारीक कटे प्याज और नमक डालकर अच्छे से चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भूनें और फिर करी पत्ता डालकर भूनें। पैन में मोठ दाल डालकर उसे अच्छे से मिलाएं। इसके बाद उसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच मिसल मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करें।

इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए ½ कप पानी डालकर धीमी आंच पर पकने दें। ऊपर से कटा बारीक धनिया डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और फिर इसको ढककर अच्छे से 2-3 मिनट के लिए पकने को छोड़ दें। वहीं तरी के लिए एक पैन में बचे हुए तेल को गर्म कर लें और पिसा हुआ मिश्रण डालकर तेल अलग होने तक भूनें। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और बचा हुआ मिसल डालकर मिक्स करें। अब इसी में 3 कप पानी डालकर 4-5 मिनट तक उबलने दें और आखिरी में नमक डालकर इसे पकने दें।

अब एक प्लेट में आलू की सब्जी डालकर ऊपर से मोठ दाल का मिश्रण डालें। फिर ऊपर से तैयार की हुई तरी डालें। इसके बाद मिसल के ऊपर फरसाण और धनिया छिड़कें। कटे प्याज, दही, नींबू और ब्रेड स्लाइस के साथ गर्मागरम परोसें।

कब है मोक्षदा एकादशी? जानें सही तिथि और पूजा विधि

सनातन धर्म में एकादशी का काफी महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत रुप से पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार, इस बार मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।

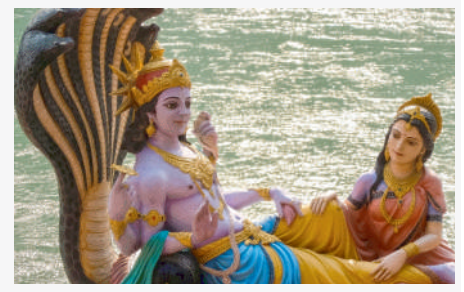

नई दिल्ली। साल में कुल 24 एकादशी की तिथियां पड़ती है और प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं। वहीं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्री विष्णु की पूजा-अर्चना की जाती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के दिन मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। दृक पंचांग के अनुसार, इस साल 11 दिसंबर को मोक्षदा एकदाशी मनाई जाएगी। माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को रखता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष दिलाने के कारण इस एकादशी को मोक्षदा एकदाशी के नाम से जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा-सामग्री व पूजा विधि।

मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर 2024 को सुबह 3.42 एएम पर शुरु होगा और अगले दिन 12 दिसंबर सुबह 01.09 ए एम पर समाप्त होगा। तो ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी।

व्रत पारण की टाइमिंग

इस बार 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, तो 12 दिसंबर 2024 को सुबह 06.57 एएम से लेकर सुबह 09 बजे तक एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं।

पूजा सामग्री लिस्ट

- श्री विष्णु जी की पूजा के लिए पीला वस्त्र जरुर होना चाहिए।
- पीले फूल, अक्षत, कुमकुम, तुलसी दल, पंचामृत, विष्णु जी और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा, आम का पत्ता, पीले फल, पंचमेवा, चौकी, धूप, दीपक सहित पूजा की सामग्री थाली में रख लें।

पूजाविधि

- इस दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान के बाद विष्णुजी का ध्यान करें।
- इसके बाद छोटी चौकी पर विष्णुजी और देवी लक्ष्मी की मूर्ति रखें।
- इसके साथ ही गणेशजी और कृष्णजी की भी प्रतिमा को रखें।
- मोक्षदा एकादशी के दिन विष्णु जी समेत सभी देवी-देवताओं को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्ध अर्पित करें। इसके बाद आरती उतारें।
- इस दिन आप व्रत रखें और एकादशी की व्रत कथा सुनें। अंत में पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए भगवान विष्णु से क्षमाप्रार्थना मांगे और आरती करने के बाद प्रसाद वितरित करें।

पूर्वोत्तर भारत-7 बहनें 1 भाई- सांस्कृतिक संपदा का प्रतीक संस्कृतिक अष्टलक्ष्मी महोत्सव 6-8 दिसंबर 2024

अष्टलक्ष्मी नाम, देवी लक्ष्मी के आठ अवतारों से प्रेरित है जो समृद्धि धन ज्ञान धर्म और कृषि आदि के प्रतीक हैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के बेहतर भविष्य का महोत्सव, जो विकसित भारत विज़न 2047 को गति देगा सराहनीय विचार–एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ को मालूम है कि भारत में प्राकृतिक संपदा, संस्कृति, संस्कारों, मानवीय बौद्धिक कौशलता, धार्मिक धर्मनिरपेक्षता हर जाति धर्म, सहित राज्य स्तरपर हर त्योहार व सांस्कृतिक समारोह विशालता से मिलजुल कर मनाए जाते हैं। आज हम इस विषय पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 से 8 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर भारत के सात बहनों व एक भाई यांने असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा और एक भाई सिक्किम मिलकर अष्ठलक्ष्मी महोत्सव मना रहेहैं, जिसका उद्घाटन 6दिसंबर 2024 को देर शाम माननीय पीएम ने किया,महोत्सव में पूर्वोत्तर के 250 से अधिक कारीगर और उद्यमीहस्तशिल्प हथकरघा और कृषि-बागवानी उत्पादों तथा 34 जीआई टैग वाले उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य विशिष्ट मंडप, एरी और मुगा सिल्क गैलरी भी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हैं। यहां महिला नेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी ऊर्जा स्वास्थ्य सेवा, खेल, कला और संस्कृति पर तकनीकी सत्र भी हुए। यह महोत्सव आठ पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक विविधता दर्शाता है इस दौरान पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक झलक दिखाई दी , जिसमें पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की एक सीरीज को साथ पेश किया गया।इस कार्यक्रम में पारंपरिक हस्तशिल्प हथकरघा, कृषि उत्पादों और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए यह कार्यक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका प्रबंधन सीपीएसई उत्तर पूर्व हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है।आठ पूर्वोत्तर राज्य- असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, ऐसे राज्य हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी या समृद्धि के आठ रूप कहा जाता है। यानि इसका कनेक्शन सेवन सिस्टर (अरुणाचल प्रदेश, असम मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) से भी है. ये भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।अष्टलक्ष्मी महोत्सव क्षेत्र की प्रगति को प्रदर्शित करने इसकी सांस्कृतिक संपदा का जश्न मनाने और भविष्य के विकास के लिए नए निवेश को आमंत्रित करने के लिए आयोजित होने वाला एक अहम कार्यक्रम है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, पूर्वोत्तर भारत-7 बहाने 1भाई, सांस्कृतिक संपदा का प्रतीक संस्कृतिक अष्टलक्ष्मी महोत्सव 6 से 8 दिसंबर 2024 तक मनाया जा रहा है।

साथियों बात अगर हम 6 से 8 नवंबर 2024 तक आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव के उद्देश्यों व महत्व की करें तो, देश के पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के बहु आयामी कपड़ा क्षेत्र, पर्यटन के अवसरों, पारंपरिक शिल्प कौशल और विशिष्ट भौगोलिक संकेत टैग वाले उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करना है, यह भारत के भविष्य के विकास के रणनीतिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र की सांस्कृतिक संपदा के उत्सवके रूपमें काम करेगा इस महोत्सव की परिकल्पना एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में की गई है जो पूर्वोत्तर भारत की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का सम्मान करना जारी रखेगा,जिससे इस क्षेत्र को और अधिक आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर किया जा सकेगा।महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व और इसके क्रांतिकारी प्रभाव पर भी जोर दिया जा रहा है, इस क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी औद्योगिक विकास और परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में चल रहेविकास से भारत की विकास कहानी में इसकी रणनीतिकभूमिका बढ़ेगी और व्यापार और व्यवसाय के लिए नए अवसर खुलेंगे। साथियों बात अगर हम माननीय पीएम उद्घाटन संबोधन में 8 लक्ष्मियों के वर्णन की करें तो,हमारी परंपरा में मां लक्ष्मी को सुख, आरोग्य और समृद्धि की देवी कहा जाता है। जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है,तो हम उनके आठ रूपों को पूजते हैं। आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी,गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी और विद्यालक्ष्मी इसी तरह भारत के पूर्वोत्तर में आठ राज्यों की अष्टलक्ष्मी विराजमान हैं। नॉर्थ ईस्ट के आठों राज्यों में अष्टलक्ष्मी के दर्शन होते हैं।अब जैसे पहला रूप है आदि लक्ष्मी। हमारे नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में आदि संस्कृति का सशक्त विस्तार है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है। मेघालय का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, नागालैंड का हॉर्नबील फेस्टिवल, अरुणाचल का ऑरेंज फेस्टिवल, मिज़ोरम का चपचार कुट फेस्टिवल, असम का बीहू, मणिपुरी नृत्य। दूसरी लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, यानि प्राकृतिक संसाधन का भी नॉर्थ ईस्ट पर भरपूर आशीर्वाद है।आप भी जानते हैं,नॉर्थ ईस्ट में खनिज, तेल, चाय के बागान और बायो-डायवर्सिटी का अद्भुत संगम है।वहां रीन्युएबल एनर्जी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है।धन लक्ष्मी का ये आशीर्वाद, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए वरदान है।तीसरी लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी की भी नॉर्थईस्ट पर भरपूर कृपा है। हमारा नॉर्थईस्ट, नैचुरल फार्मिंग के लिए, जैविक खेती के लिए, मिलेट्स के लिए प्रसिद्ध है। हमें गर्व है कि सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। नॉर्थ ईस्ट में पैदा होने वाले चावल, बांस, मसाले और औषधीय पौधे,वहां कृषि की शक्ति को दिखाते हैं। आज का भारत, दुनिया को हेल्दी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए न्युट्रिशन से जुड़े हुए, जो सोल्यूशन देना चाहता हैउसमें नॉर्थ ईस्ट की बड़ी भूमिका है।अष्टलक्ष्मी की चौथी लक्ष्मी हैं,गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी कमल पर विराजमान हैं और उनके आसपास हाथी हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में विशाल जंगल हैंकाजीरंगा मानस मेहाओ जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वहां अद्भुत गुफाएं हैं, आकर्षक झीलें हैं। गजलक्ष्मी का आशीर्वाद नॉर्थ ईस्ट को दुनिया का सबसे शानदार टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का सामर्थ्य रखता है।पांचवीं लक्ष्मी हैं, संतान लक्ष्मी यानि उत्पादकता की, क्रिएटिविटी की प्रतीक। नॉर्थ ईस्ट, क्रिएटिविटी के लिए, स्किल के लिए जाना जाता है।जो लोग यहां एग्ज़ीबिशन में जाएंगे, हाट बाज़ार में जाएंगे।उन्हें नॉर्थ ईस्ट की क्रिएटिविटी दिखेगी।हैंडलूम्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का ये हुनर सबका दिल जीत लेता है। असम का मुगा सिल्क, मणिपुर का मोइरांग फी, वांखेई फी, नागालैंड की चाखेशांग शॉल।ऐसे दर्जनों हैं जो नॉर्थ ईस्ट की क्राफ्ट को, क्रिएटिविटी को दिखाते हैं।अष्टलक्ष्मी की छठी लक्ष्मी हैं वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी यानि साहस और शक्ति का संगम। नॉर्थ ईस्ट, नारी-शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक है। मणिपुर का नुपी लान आंदोलन, महिला-शक्ति का उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं ने कैसे गुलामी के विरुद्ध बिगुल फूंका था, ये हमेशा भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज रहेगा। रानी गाइदिन्ल्यु, कनकलता बरुआ, रानी इंदिरा देवी, ललनु रोपिलियानी लोक गाथाओं से लेकर हमारी आज़ादी की लड़ाई तक, नॉर्थ ईस्ट की नारीशक्ति ने पूरे देश को प्रेरणा दी है। आज भी इस परंपरा को नॉर्थ ईस्ट की हमारी बेटियां समृद्ध कर रही हैं। यहां आने से पहले मैं जिन स्टॉल्स में गया, वहां भी अधिकतर महिलाएं ही थीं। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं की इस उद्यमशीलता से पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक ऐसी मजबूती मिलती है, जिसका कोई मुकाबला नहीं।अष्टलक्ष्मी की सातवीं लक्ष्मी हैंजय लक्ष्मी। यानि ये यश और कीर्ति देने वाली हैं। आज पूरे विश्व में भारत प्रति जो उम्मीदें हैं, उसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट की अहम भूमिका है। आज जब भारत, अपने कल्चर, अपने ट्रेड की ग्लोबल कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहा है,तब नॉर्थ ईस्ट, भारत को साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के असीम अवसरों से जोड़ता है।अष्टलक्ष्मी की आठवीं लक्ष्मी है,विद्या लक्ष्मी यानि ज्ञान और शिक्षा। नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिल चुका है। देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में ही बन रही है। मैरी कॉम, बाइचुंग भूटिया, मीराबाई चानू, लोवलीना सरिता देवी ऐसे कितने हीस्पोर्ट्स पर्सन नॉर्थ ईस्ट ने देश को दिए हैं। आज नॉर्थ ईस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्ट अप्स, सर्विस सेंटर्स और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों में भी आगे आने लगा है। इनमें हज़ारों नौजवान काम कर रहे हैं। यानि "विद्या लक्ष्मी" के रूप में ये रीजन, युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल का बड़ा केंद्र बन रहा है।

(अतः अगर हम अपने पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पूर्वोत्तर भारत - 7 बहनें 1 भाई- सांस्कृतिक संपदा का प्रतीक संस्कृतिक अष्टलक्ष्मी महोत्सव 6-8 दिसंबर 2024 अष्टलक्ष्मी नाम, देवी लक्ष्मी के आठअवतारों से प्रेरित है जो समृद्धि धन ज्ञान धर्म और कृषि आदि के प्रतीक हैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के बेहतर भविष्य का महोत्सव, जो विकसित भारत विज़न 2047 को गति देगा सराहनीय विचार)

-क्रर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

विंटर में रोजाना सुबह गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीने से शरीर को मिलते हैं गजब के बेनिफिट्स

विंटर सीजन में गर्म और आरामदायक रहने की मांग करता है। दिन की अच्छी शुरुआत के लिए आप सुबह के समय गर्म या गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीना एक हेल्दी ड्रिंक मानी जाती है।

अगर आप सर्दी की सुबह गर्म पानी के साथ नींबू पानी पीते हैंस तो शरीर को कई फायदे मिलते हैं। विंटर में खुद को स्वस्थ रखने के लिए गर्म पानी के साथ नींबू का पानी जरुर पीना चाहिए।

सर्दियों में गर्म पानी में नींबू मिलाकर पानी पीने के फायदे

विटामिन सी प्रदान होता है

नींबू में सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। सर्दियों के दौरान, जब सर्दी और फ्लू होने का खतरा ज्यादा रहता है, तो ऐसे में विटामिन सी का सेवन बढ़ाने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। एक अध्ययन के मुताबिक, विटामिन सी श्वसन संक्रमण की अवधि और गंभीरता को कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत गर्म नींबू पानी से करें।

पाचन में सहायक

नींबू के साथ गर्म पानी स्वस्थ पाचन को बढ़ावा दे सकता है। नींबू के रस क जो गैसट्रिक एसिड के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद करती है, जो भोजन को पचाने के लिए आवश्यक है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि बेहतर पाचन से सूजन और असुविधा सहित अपच के लक्षणों को कम किया जा सकता है। इस मिश्रण को खाली पेट पीने से आपके पाचन तंत्र को अगले दिन के लिए तैयार करने में मदद मिल सकती है।

शरीर को हाइड्रेट रखता है

सर्दी के समय खुद को हाइड्रेट रखना काफी महत्वपूर्ण रखना जरुरी है। बाहर की ड्राइ हवा और ठंडे मौसम से डिहाइड्रेशन हो सकता है। सुबह गर्म नींबू पानी पीने से बॉडी का समग्र कल्याण होता है।

वजन कंट्रोल करता है

गर्म नींबू पानी वजन प्रबंधन में भी सहायता कर सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि भोजन से पहले नींबू पानी पीने से कैलोरी की मात्रा कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, नींबू में पेक्टिन फाइबर होता है, जो तृप्ति की भावना को बढ़ावा दे सकता है। एपेटाइट में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि पानी के अधिक सेवन से भूख कम हो सकती है और वजन घटाने के परिणामों में सुधार हो सकता है।

महिलाओं पर बढ़ता बोझ: परिवार नियोजन में पुरुषों की कम भागीदारी

कई पुरुष इसे अपनी रमर्दानगीर पर आघात मानते हैं। वहीं, पारंपरिक धारणाएँ और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी ने भी इस प्रक्रिया को अपनाने में रुकावटें खड़ी की हैं। पुरुष नसबंदी महिलाओं की तुलना में एक सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है। इसे अपनाने से न केवल महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ कम होंगी, बल्कि समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत को चाहिए कि वह शिक्षा, जागरूकता, और आर्थिक प्रोत्साहन के माध्यम से परिवार नियोजन को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करे। परिवार केवल महिलाओं का दायित्व नहीं है। पुरुषों की भागीदारी से परिवार नियोजन अधिक सफल और संतुलित हो सकता है।

-प्रियंका सौरभ

भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी, जिसका उद्देश्य नसबंदी जैसे तरीकों के ज़रिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था। वर्षों के साथ, इस पहल ने जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायित्व की दिशा में प्रगति की। हालांकि, गर्भनिरोधक उपायों में पुरुष नसबंदी जैसे सरल और सुरक्षित विकल्प मौजूद होने के बावजूद, यह आज भी सामाजिक स्तर पर व्यापक स्वीकृति हासिल नहीं कर पाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पुरुष नसबंदी प्रक्रियाओं का केवल 0.3% हिस्सा है। नीतिगत प्रयासों के बावजूद, नसबंदी दरों में एक महत्त्वपूर्ण लैंगिक असमानता है, जिसमें सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं के कारण महिलाओं को ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है। 1952 से अग्रणी परिवार नियोजन कार्यक्रमों के बावजूद, भारत में नसबंदी दरों में एक महत्त्वपूर्ण लैंगिक असमानता है। नसबंदी दरों में लैंगिक असमानता और गर्भनिरोधक में पुरुषों की कम भागीदारी के पीछे सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड हैं। भारत में पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ अक्सर परिवार नियोजन को मुख्य रूप से महिला की ज़िम्मेदारी मानती हैं। सर्वेक्षणों से पता चला है कि नसबंदी के लिए मुख्य रूप से महिलाएँ ज़िम्मेदार हैं, जबकि पुरुष पुरुषत्व और अहंकार की चिंताओं के कारण इसका विरोध करते हैं, जिससे नसबंदी कम स्वीकार्य हो जाती है।

बहुत से पुरुष-पुरुष नसबंदी के लिए उपलब्ध विकल्पों जैसे कि पुरुष नसबंदी के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं दोनों में अक्सर नो-स्केलपेल पुरुष नसबंदी के बारे में जागरूकता की कमी होती है, जो कि कम आक्रामक और सुरक्षित विकल्प है, जिसके कारण कम पुरुष इस प्रक्रिया को चुनते हैं। वेतन हानि का डर और दैनिक आय पर नसबंदी के प्रभाव के कारण पुरुष इस प्रक्रिया को चुनने से हतोत्साहित होते हैं। वेतन हानि की भरपाई के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले नकद प्रोत्साहन का उपयोग सूचना के खराब प्रसार के कारण कम किया जाता है, जिससे कई पुरुष उपलब्ध वित्तीय सहायता से अनभिज्ञ रह जाते हैं। व्यापक धारणा है कि पुरुष नसबंदी वास्तव में जितनी जोखिम भरी है, उससे कहीं ज़्यादा जोखिम भरी है, जिसके कारण पुरुष इस प्रक्रिया को अपनाने से कतराते हैं। पुरुष नसबंदी की सुरक्षा के बारे में ग़लत जानकारी, जिसमें साइड इफ़ेक्ट और जटिलताओं का डर शामिल है, अक्सर पुरुषों को इस प्रक्रिया पर विचार करने से रोकती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की कमी है, जिससे पुरुष नसबंदी प्रक्रियाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है।

भारत के नसबंदी कार्यक्रम में चुनौतियाँ सूचित सहमति का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाओं पर नसबंदी प्रक्रियाओं के निहितार्थों को पूरी तरह समझे बिना दबाव डाला जाता है या उन्हें इसके लिए मजबूर किया जाता है। 2014 में छत्तीसगढ़ में हुए कुख्यात नसबंदी कांड में, जहाँ एक असफल नसबंदी शिविर के बाद 15 महिलाओं की मौत हो गई थी, सूचित सहमति के प्रति उपेक्षा को उजागर किया। नसबंदी प्रक्रियाएँ अक्सर अपर्याप्त नसबंदी प्रथाओं के साथ खराब सुसज्जित स्वास्थ्य सुविधाओं में की जाती हैं, जिससे संक्रमण और जटिलताएँ होती हैं। नसबंदी के लिए सरकारी लक्ष्य अक्सर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर कोटा पूरा करने का दबाव डालते हैं, जिससे देखभाल की गुणवत्ता और नैतिक विचारों से समझौता होता है। नसबंदी महिलाओं के लिए असंगत रूप से लक्षित है, जो लैंगिक असमानता को क़ायम रखती है और प्रजनन विकल्पों को सीमित करती है। NFHS-4 (2015-16) के अनुसार, महिला नसबंदी 37.9% है, जबकि पुरुष नसबंदी केवल 0.3% है, जो भारत में नसबंदी जिम्मेदारियों के विषम वितरण को उजागर करता है। नसबंदी करवाने वाली महिलाओं को सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके आत्मसम्मान और कल्याण को प्रभावित करता है। जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने पुरुष नसबंदी के लिए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कार्यान्वयन धीमा है। नीतिगत पहलों के बावजूद, परिवार नियोजन कार्यक्रमों में पुरुषों की भागीदारी को रोकने वाली बाधाओं को दूर करने पर अपर्याप्त ध्यान देने के कारण पुरुष नसबंदी की दरें स्थिर हो गई हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 30% पुरुष नसबंदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय जागरूकता और शिक्षा में वृद्धि। पुरुष नसबंदी की सुरक्षा और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रित शैक्षिक अभियान अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सूचना अभियानों को नो-स्केलपेल नसबंदी के लाभों पर ज़ोर देना चाहिए, इसकी सुरक्षा और न्यूनतम रिकवरी समय पर प्रकाश डालना चाहिए। पुरुषों को नसबंदी का विकल्प चुनने के लिए अधिक आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन देना भागीदारी बढ़ा सकता है। नसबंदी सेवाओं तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढाँचा बनाना आवश्यक है। पुरुष नसबंदी प्रक्रियाओं में अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना पुरुषों के लिए सेवाओं तक पहुँच को आसान बना देगा। परिवार नियोजन पहलों को सीधे पुरुषों को लक्षित करना चाहिए, पुरुष नसबंदी और अन्य पुरुष गर्भनिरोधक विधियों को बढ़ावा देना चाहिए। अधिक पुरुषों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुरुषत्व और परिवार नियोजन के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण को चुनौती देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक अभियानों को सामाजिक धारणाओं को बदलने के लिए काम करना चाहिए, यह दिखाते हुए कि पुरुष नसबंदी पुरुषों के लिए एक ज़िम्मेदार और सशक्त विकल्प है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 2025 तक 30% पुरुष नसबंदी के लक्ष्य को प्राप्त करना परिवार नियोजन में लैंगिक समानता के लिए महत्त्वपूर्ण है। सांस्कृतिक, आर्थिक और अवसंरचनात्मक बाधाओं को सम्बोधित करने से पुरुष भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। अन्य देशों की सर्वोत्तम प्रथाएँ, जैसे सामुदायिक नेता भागीदारी और लक्षित शिक्षा, प्रगति को गति देंगी।

शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण दिल्लीवालें परेशान है, लोग अपने घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं करते-सीएम आतिशी

सुषमा रानी

नईदिल्ली। सीएम आतिशी ने शनिवार को एम्स ट्रामा सेंटर में गोविंदपुरी में हुई चाकूबाजी के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। चाकूबाजी के कारण परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है।

इस मौके पर सीएम आतिशी ने कहा कि, ₹भाजपा शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह ब्रेक डाउन कर दिया है। केंद्र सरकार की दिल्ली में बस एक जिम्मेदारी दिल्लीवालों को सुरक्षा देना है लेकिन भाजपा इसमें भी पूरी तरह फेल हो गई है।

उन्होंने कहा कि, शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण दिल्लीवालें परेशान है, लोग अपने घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं करते जबकि शहर में अपराधी बेख़ौफ़ घूम रहे है उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। सीएम आतिशी ने कहा कि, दिल्ली में लोगों को सुरक्षा देने का भाजपा शासित केंद्र सरकार अपना काम ठीक से करें वरना सबक सिखाने के लिए सभी दिल्ली के लोगों को साथ आना पड़ेगा*

सीएम आतिशी ने मीडिया से साझा करते हुए कहा कि,₹गोविंदपुरी में आज सुबह हुई चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसकी कई घंटों की सर्जरी चल रही है। उन्होंने कहा कि, ये वही इलाका है जहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर दो हफ़्ते पहले एक ऑन ड्यूटी बीट कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि, आज सुबह शाहदरा इलाके में भी सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति पर गोलियाँ चल गई।₹

सीएम आतिशी ने कहा कि, ₹मैं ये जानना चाहती हूँ कि, केंद्र सरकार क्या कर रही है। भाजपा शासित केंद्र सरकार की दिल्ली में बस एक

जिम्मेदारी है, और वो है दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को संभालना, दिल्लीवालों को सुरक्षा देना। लेकिन भाजपा इसमें भी पूरी तरह फेल हो गई है। रोज़ कभी किसी की हत्या हो रही है, कभी गोलीबारी हो रही है, कभी किडनैपिंग की घटना हो रही है, कभी किसी को फिरौती की कॉल आ रही है।"

उन्होंने कहा कि, भाजपा शासित केंद्र सरकार ने आज दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह ब्रेक डाउन कर दिया है। दिल्लीवालें परेशान है। कोई अपने घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं करता, रेस्टोरेंट में गोलियाँ चल रही है, गाड़ी के शोरूम में गोलियाँ चल रही है, मॉर्निंग-वॉक करने जा रहे लोगों पर गोलियाँ चल रही है, घरों के अंदर चाकूबाजी हो रही है। आज अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है कि हमनें कुछ ग़लत किया तो पकड़े जाएँगे।₹

सीएम आतिशी ने कहा कि, ₹मैं भाजपा शासित केंद्र सरकार को कहना चाहूँगी कि, आपके पास दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने का एक काम है। आप अपना काम ठीक तरह से करिए वरना आपको अपनी सही जगह दिखाने के लिए सभी दिल्ली के लोगों को साथ आना पड़ेगा।"

दिल्ली की जनता से अपील है कि इस बार बहुत सोच समझकर वोट देना, भाजपा ने अपनी मंशा साफ़ कर दी है : केजरीवाल

सुषमा रानी

नईदिल्ली। दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किए गए नारे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर कहा कि आज बीजेपी ने नारा दिया है - बदल के रहेंगे। हमें जिसका डर था, वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि अगर इनको वोट दे दिया तो दिल्ली की जनता के साथ मिलकर दस साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, वो सब काम ये लोग बंद कर देंगे। आज भाजपा ने अधिकारिक तौर पर एलान कर दिया कि वे सब कुछ बदल देंगे। यानि 24 घंटे बिजली बंद हो जाएगी, फिर लंबे लंबे पॉवर कट लगने लगेंगे, फ्री बिजली बंद हो जाएगी और हजारों रुपए महीने के बिजली बिल आने लगेंगे। महिलाओं का फ्री बस सफ़र बंद हो जाएगा, सभी सरकारी स्कूल फिर से बर्बाद हो जाएंगे, सभी मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए जाएंगे और सभी सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली फ्री दवाइयां और इलाज बंद हो जाएगा। इसलिए दिल्ली की जनता से अपील है कि इस बार बहुत सोच समझकर वोट देना। भाजपा ने अपनी मंशा साफ़ कर दी है।

अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पिछले दस साल से हमने पूरी मेहनत से दिल्ली के दो करोड़ लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे काम किए हैं। पहले दिल्ली में बिजली के लंबे-लंबे पावर कट लगते थे, लेकिन अब 24 घंटे बिजली आती है। पहले दिल्ली में हर महीने हजारों रुपए के बिजली के बिल आया करते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोगों के जीरो बिल आते हैं और बाकी लोगों को बहुत सस्ती बिजली मिलती है। दिल्ली में शिक्षा में काफी सुधार हुआ है। हमने सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए हैं। अब मिडल क्लास भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज

रहे हैं। हमने सरकारी अस्पतालों की स्थिति में भी काफी सुधार किया है। पूरी दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लीनिक बनाया है। जहां सर इलाज मुफ्त होता है। सरकारी अस्पतालों सबका इलाज मुफ्त है। आज दिल्ली के लोगों को हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त मिलता है। महिलाओं का बस में सफर मुफ्त है। हमारी सरकार बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा करवाती है।

उनका कहना है कि भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे उन सभी कामों को रोकने के लिए हर तरह का षडयंत्र करती रही है। दिल्ली की जनता को मिल रही मुफ्त बिजली को रोकने का कई बार प्रयास किया, लेकिन हमने इनके षड्यंत्रों को हर बार नाकाम किया। अब आज तो इन लोगों ने खुद ही आधिकारिक तौर पर एलान कर दिया है कि सबकुछ बदल देंगे। इनके कहने का साफ मतलब यही है कि दिल्ली की जनता ने गलती से भी इनको वोट दे दिया और ये सरकार में आ गए तो सबसे पहले ये लोग आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा जनता को मिल रही मुफ्त सुविधाओं को बंद करेंगे। यानी कि ये लोग 24 घंटे और मुफ्त मिल रही बिजली बंद कर देंगे। फिर दिल्लीवालों को लंबे लंबे पावर कट का सामना करना पड़ेगा। ये लोग बिजली महंगी कर देंगे, लोग बिल नहीं भर पाएंगे। स्कूलों का बेड़ा गर्क कर देंगे। फिर सरकारी स्कूल दस साल पहले जैसे हो जाएंगे। मुफ्त पानी बंद कर देंगे, महिलाओं का बस में मुफ्त सफर बंद कर देंगे, बुजुर्गों की तीर्थयात्रा बंद कर देंगे। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज बंद कर देंगे। इसलिए दिल्ली की जनता को बहुत ही सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है, उसे जारी रखने के आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए।

दिल्ली चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने दिया नया नारा, BJP दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर

दिल्ली चुनाव 2025 से पहले भाजपा ने नया नारा दिया है – अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। भाजपा का यह नारा लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है जो भ्रष्ट सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं। यह बातें भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कही। सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

नई दिल्ली। शनिवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय के बाहर 'अब नहीं सहेंगे, बादल के रहेंगे' नारे वाले पोस्टर लगाए गए। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह नारा लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो भ्रष्ट सरकार को सत्ता से हटाने की उनकी इच्छा व्यक्त करता है।

यह नारा दिल्ली के लोगों की आवाज-वीरेंद्र सचदेवा

एएनआई से बात करते हुए सचदेवा ने कहा कि 'अब नहीं तो सहेंगे, बादल के रहेंगे' का नारा दिल्ली के लोगों की आवाज है। जब हमने बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांगे, तो लोगों ने कहा कि वे भ्रष्ट दिल्ली सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि दिल्ली की जनता टूटी सड़कों, गंदे पानी और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है, जनता दिल्ली का विकास चाहती है। बीजेपी जब डबल इंजन सरकार करेगी तभी दिल्ली विकास की राह पर आगे बढ़ेगी। इसके अलावा, सचदेवा ने रिठाला-नरेला-नाथूपुर (कुंडली) कॉरिडोर पर भी टिप्पणी की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मंजूरी दी थी।

मेट्रो रूट का विस्तार मजदूरों और लोगों के लिए फायदेमंद-भाजपा

सचदेवा बोले कि स्वीकृत मेट्रो रूट वास्तव में मजदूरों और लोगों के लिए फायदेमंद होगा। प्रधानमंत्री (PM Modi) दिल्ली को बेहतर बनाने और बेहतर बनाने के लिए नई पहल कर रहे हैं। अब दिल्ली को बेहतर बनाना जरूरी है और डबल इंजन की सरकार जरूर बनेगी। 26.463 किमी लंबे मेट्रो कॉरिडोर से दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है।

रिठाला-कुंडली कॉरिडोर परिचालन शहीद स्थल (ब्लू बस अड्डा)-रिठाला (रेड लाइन) कॉरिडोर का विस्तार होगा। एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि नया विस्तार 21 एलिवेटेड स्टेशनों को कवर करेगा, जो दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में नरेला, बवाना और रोहिणी के कुछ हिस्सों को जोड़ेगा।

"यमुना प्राधिकरण की नई आवासीय योजना: 451 प्लॉट्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी"

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने हाल ही में 451 आवासीय प्लॉटों की योजना शुरू की है, जिसमें 120, 162, 200, 250 और 260 वर्गमीटर के प्लॉट शामिल हैं। इन प्लॉटों के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2024 से शुरू हुई थी, और आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत, 1,11,852 आवेदकों ने आवेदन किया है, जिसमें सबसे अधिक 48,196 आवेदन 200 वर्गमीटर के प्लॉटों के लिए प्राप्त हुए हैं। इसके बाद, 162 वर्गमीटर के प्लॉटों के लिए 36,464 और 120 वर्गमीटर के प्लॉटों के लिए 24,026 आवेदन आए हैं। पिछली योजना की तुलना में, इस बार आवेदन संख्या में कमी आई है; पिछली योजना में 2 लाख से अधिक आवेदन 361 प्लॉटों के लिए आए थे।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है आवेदकों को YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन शुल्क शामिल हैं। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए, YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी के चेयरमैन भाई मेहरबान कुरैशी के प्रयासों से व्यापारियों को मिली एटीएम सुविधा

सुषमा रानी

नई दिल्ली। मुर्गा मछली मंडी समिति दिल्ली सरकार के चेयरमैन भाई मेहरबान कुरैशी के कर कमलों द्वारा मंडी परिसर में बैंक ऑफ़ बड़ौदा का एटीएम स्थापित किया गया। उद्घाटन अवसर पर समिति के सचिव आनंद शाही, ट्रेफिक पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पेन्द्र यादव, नज़ीर फ़ूडस के चेयरमैन हाजी आफ़ताब कुरैशी, फ़ेस ग्रुप के चेयरमेन डॉ० मुश्ताक़ अंसारी, चौधरी निजामुद्दीन क़ुरैशी, बिलाल क़ुरैशी, हाजी सलाउद्दीन, रज़िया बेगम, मौहम्मद इमरान क़ुरैशी, जावेद क़ुरैशी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौक़े पर हाजी मेहरबान कुरैशी ने कहा कि मंडी परिसर में एटीएम सुविधा उपलब्ध होने से व्यापारियों को काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि यहाँ आसपास दूर दूर तक बैंक या एटीएम नहीं है। हाजी आफ़ताब क़ुरैशी ने कहा कि भाई मेहरबान कुरैशी व्यापारियों की समस्याओं के प्रति गंभीरता दिखाते हुए जल्द समाधान करते हैं। हाजी चौधरी निज़ाम ने कहा की भाई मेहरबान कुरैशी के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं।

बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जिम्मेदारी के चलते मुख्यमंत्री आतिशी का इस्तीफा क्यों नही लेते? - यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि खौफ में जीने को मजबूर दिल्लीवासियों की रक्षा और सुरक्षा करने की बजाय सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायक बनने की बजाय दिल्ली के नागरिकों का मनोबल कम करने के लिए हर वो संभव कोशिश कर रहे है जिसके अरविन्द केजरीवाल भाजपा सरकार के साथ राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए बराबर के जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वही केजरीवाल है जो एक निर्भया कांड पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से इस्तीफा मांगते थे, प्रतिदिन औसतन 4-5 बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जिम्मेदारी लेकर केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का इस्तीफा क्यों नही मांगते? उन्होंने कहा कि अपराध में नम्बर वन राजधानी दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे है। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल स्वयं बसें और मेट्रों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आश्वस्त नही है, जबकि महिला सुरक्षा के लिए लगाए गए 50 प्रतिशत अधिक सीसीटीवी कैमरे काम ही नही करते? बसों के पैनिक बटन फेल होने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, अरविन्द केजरीवाल इस पर चुप क्यों है? उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा घोषित 90 हजार स्ट्रीट के बदले एलईडी लगाने के वायदे का क्या हुआ, जबकि दिल्ली के रिहायशी इलाकों की सड़कों पर अंधेरी और असुरक्षित हैं।

यादव ने कहा कि राजधानी में बढ़ते गैंगवार, गोलीबारी, हत्या, बलात्कार, यौन शोषण और झपटममारी की घटनाओं में सबसे ज्यादा हर्जाना महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। महिलाओं को बाहर निकलते के साथ उन्हें हमेशा अपनी जान और सामान की चिंता रहती है, बसों, मेट्रो, रिक्शा, पार्क, सड़क कहीं भी सुरक्षित नही है। यहां तक की घरों में भी असुरक्षित महसूस करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा का बेटी पढ़ाओं बेटी बचाओं का नारा पूरी तरह खत्म हो गया है। जब बेटी घर से बाहर निकलेगी तो अत्याचार और उत्पीड़न को झेलेगी, फिर कहां पढ़ेगी। भाजपा सरकार का गृह मंत्रालय दिल्ली की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल हो गया है, गृहमंत्री अमित शाह अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें।

उन्होंने कहा कि शाहदरा, गोविंदपुरी, पिछले हफ्ते नेब सराय में हुई घटनाएं दिल्ली की मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार और भाजपा की केन्द्र सरकार की अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में निष्क्रियता को दर्शाती है। यादव ने कहा कि अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय भाजपा नेता और अरविन्द केजरीवाल कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कोई बात नही करते, दोनो कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है इस पर बोलते है। मैं पूछना चाहता हूँ अरविन्द केजरीवाल से 2013 में उन्होंने किस बुनियाद पर दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया था कि हमें सत्ता में लाओं, दिल्ली की कानून व्यवस्था दुरस्त कर देंगे। बिगड़ती कानून व्यवस्था में बराबर की जिम्मेदारी लेते हुए अरविन्द केजरीवाल आतिशी से इस्तीफा क्यों नही लेते।

युवा पीढ़ी को हिंसा, नफरत, असहिष्णुता, और वासना से अभी बचाना जरूरी

भूपेन्द्र गुप्ता-विभूति फीचर्स

मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव में जहां पर संस्कृति और संस्कार की पकड़ समाज पर गहन होती है वहां एक छात्र द्वारा अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल को गोली मार देने की घटना देश को हिला देने वाली है।भारत के पिछले 100 साल के ज्ञात इतिहास में संभवतः यह पहली घटना है, जहां पर एक छात्र ने अपने प्रिंसिपल को गोली से भून डाला है। इसी समय मध्य प्रदेश के एक दूसरे गांव गरोठ में दलित परिवार द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए एक दबंग ने गोली से महिला मजदूर को भून दिया है। एक और घटनाक्रम में स्कूल के सहपाठी चार नाबालिगों ने एक बच्ची से गैंगरेप किया फिर उसे ब्लैकमेल किया और अंततोगत्वा उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली।

समाज में इतनी हिंसा, इतनी नफरत, इतनी असहिष्णुता,इतनी वासना कहां से आ रही है? क्या हमारा समाज अपने मूल्यों को बचाने में असफल हो रहा है ? क्या घृणा के दो छोर इतने कठोर हो चुके हैं कि अब शिष्य और गुरु के बीच में भी गोली ही अंतिम उपाय रह गया है।

समाज के रूप में अगर हम भारत को देखें तो यह गन कल्चर हमने अमेरिका में तो सुना था जहां पर बच्चे स्कूल के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं । यह हमने पाकिस्तान में भी सुना था लेकिन भारत में इस घटना का होना दर्शाता है कि समाज में जंग लग रही है और हमारा सिस्टम हमारी मूल्यानुगत परंपराएं इस उन्माद का समाधान खोजने में असमर्थ हैं ।

भारत के गांवों का हम अध्ययन करें तो पाते हैं कि विगत 10 वर्षों में गली कूचों और देहातों में जिन गरीब

बस्तियों में ना तो नियमित रोजगार है न ही अतिरिक्त आमदनी , वहां भी आधा गांव नशे में डूबा है। नशीले पदार्थों का सेवन, धर्म, और जाति का नशा और इसकी फंडिंग राज्य को तो असफल कर ही रही है ,समाज के रूप में भी हमें असफल कर रही है।

हम 10 वर्ष पहले यह दम भरने वाले राष्ट्र थे कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी 50 फीसदी आबादी युवा है और हम दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं ।

हमारे इन दावों को तीन तरह से दुनिया के शैतानों ने तोड़ दिया है।

एक- इन नौजवानों के हाथ में काम मत जाने दो उनकी जवानी नौकरी रोजगार खोजते खोजते ही समाप्त हो जाए।

दो- शिक्षा पर हमला करो ताकि योग्यता और युवावस्था का सामंजस्य ना रहे ।

तीन- इस बेरोजगार नौजवान को नशे के दलदल में उतार दो जहां पर वह अपनी दुनिया से अनुपस्थित हो जाए।

क्या भारत इस खतरे को भांप रहा है कि जिस जवानी पर वह दस साल पहले नाज कर रहा था आज उसके पांव लड़खड़ा रहे हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में 40 फीसदी भी रोजगार के हिसाब से योग्य नहीं हैं। एम्प्लायबिलिटी का यह संकट दिखाई पड़ना चाहिये।

इसके पहले चीन भी स्मार्ट सिटी के चक्कर में फंसकर बहुत कुछ गंवा चुका है। वे शहर अब घोस्ट सिटी(भुतहा शहर) के रूप में जाने जाते हैं। चीन ने अपने आपको मास प्रोडक्शन और मेनपावर के नियोजन से बचा लिया है । हमें भी समय रहते यह करना होगा।

भारत की युवा पीढ़ी सामर्थ्यवान है। क्या एक राष्ट्र के रूप में इस मानव संसाधन(ऊर्जा) को हम नियमित कर पा रहे हैं? क्या हम उसे क्षमतावान संसाधन के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं।

शायद नहीं..।आज आवश्यकता है कि सरकारें देश को इस तिहरे नागपाश से बचाने के लिये राष्ट्रीय नीति का निर्माण करें। यह नीति निम्न उपायों पर केंद्रित होकर मिशन मोड में क्रियान्वित हों-

नौजवान बेरोजगारों को समयबद्ध तरीके से रोजगार से जोड़कर देश की उत्पादकता बढाने के उपाय।

देश में लाखों-करोड़ मूल्य के नशे के प्रवेश से समाज के विघटन को रोकने के उपाय।

नशे के स्रोत और उसकी फंडिंग के मूल पर आक्रमण के उपाय।

शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उपाय ।

नियोजनीयता कौशल के विकास को बढ़ाना।

अपराध ,अराजकता ,धर्म और जाति का उन्माद तथा कार्यकुशलता का अभाव इतने बड़े देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। चमचमाती हुई सड़कें तो कल भी बन सकती हैं लेकिन एक मुर्दा होती पीढ़ी को आज और इसी वक्त बचाना जरूरी है।

स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आयोजन समिति का गठन किया

सुषमा रानी

नई दिल्ली वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब की एक महत्वपूर्ण बैठक कूचा चेलान स्थित हाजी जहूर अटैची वाला के कार्यालय पर हुई। सीनियर क्राइम रिपोर्टर अमीर अहमद राजा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गयी. शीर्ष एजेंडे में क्लब का स्थापना दिवस था। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थापना दिवस के अवसर पर गरिमामय एवं भव्य समारोह का आयोजन किया जायेगा. यह कार्यक्रम दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पत्रकारों को पुरस्कृत करने के अलावा प्रमुख पत्रकारिता, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और साहित्यिक हस्तियों को आमंत्रित किया जाएगा।

स्थापना दिवस समारोह की रूपरेखा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता फरजान कुरैशी करेंगे, जबकि इसमें अमीर अहमद राजा, मनोज टंडन, मुहम्मद तस्लीम और मुहम्मद गुलजार को शामिल किया गया. इसके अलावा क्लब द्वारा आयोजित मेडिकल कैंप, रोजगार मेले के आयोजन एवं सहयोगी सदस्य बनाने के संबंध में भी सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की. बैठक की शुरुआत अमीर अहमद राजा द्वारा पवित्र कुरान के पाठ से हुई और प्रार्थना के साथ समाप्त हुई। अंत में क्लब के अध्यक्ष फ़रज़ान कुरैशी ने मेज़बान हाजी ज़हूर अटैची वाला को धन्यवाद दिया। बैठक में नईम मलिक, मुहम्मद फैजान, हसनैन अख्तर, असद मियां, क्लब अध्यक्ष फरजान कुरैशी के अलावा सदस्य मुहम्मद ओवैस, अमीर अहमद राजा, मनोज टंडन, अहमद नौमान, मुहम्मद रहीम, ऐन अली हक भी मौजूद रहे। नरेंद्र कुमार, सुषमा रानी. मुहम्मद गुलजार, फजील अहमद, मुहम्मद तसलीम, वाहिदुर्रहमान उस्मानी मौजूद रहे।

सामाजिक कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और संभल हिंसा के खिलाफ हर न्यायप्रिय नागरिक को आवाज उठानी चाहिए

सुषमा रानी

दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मलिक मोअतासिम खान, उपाध्यक्ष, जमात-ए-इस्लामी हिंद ने कहा कि ₹सभी इबादतगाहों के 15 अगस्त, 1947 की यथास्थिति सुनिश्चित करके सांप्रदायिक तनाव को रोकने के इरादे से उपासना स्थल अधिनियम, 1991 को अधिनियमित किया गया था। इस महत्वपूर्ण कानून का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना तथा इबादतगाहों पर ऐतिहासिक दावों को लेकर विभिन्न विवादों को बढ़ने से रोकना था। कानून के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, हम मस्जिदों, दरगाहों और अन्य धार्मिक स्थलों के बारे में झूठे, निराधार और राजनीति से प्रेरित दावे देखते रहते हैं। दुर्भाग्यवश, ये मनगढ़ंत दावे अदालतों में दायर याचिकाओं में अपना रास्ता खोज लेते हैं, और कुछ मामलों में इन शरारती याचिकाओं को खारिज करने के बजाय, कभी-कभी अदालतें इन मुस्लिम इबादतगाहों का सर्वेक्षण या अध्ययन करने की अनुमति दे देती हैं। इससे उपासना स्थल अधिनियम की मूल भावना कमजोर होती है तथा अनावश्यक विवाद, सांप्रदायिक अशांति और यहां तक कि हिंसा भी बढ़ती है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद इस विक्षुब्ध करने वाली प्रवृत्ति से बेहद चिंतित है और मांग करती है कि पूजा स्थल अधिनियम को अक्षरशः और उसकी भावना से लागू किया जाना चाहिए। अदालतों को ऐसी दुर्भावनापूर्ण याचिकाओं को खारिज करना चाहिए जिनका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना हो।

भारत में बेरोजगारी: आंकड़े और वास्तविकता

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

भारत में बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है, और हाल के आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, जितनी सरकार दावा कर रही है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत पर स्थिर है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कहीं अधिक चिंताजनक है।

युवाओं में बेरोजगारी

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बेरोजगारों में 80 प्रतिशत युवा हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि हमारे युवा, जो देश का भविष्य हैं, आज भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। पिछले दो दशकों में युवाओं में बेरोजगारी दर 30 प्रतिशत बढ़ गई है, जो कि बेहद चिंताजनक है।

महिलाओं की स्थिति

महिलाओं की बेरोजगारी दर पुरुषों से अधिक है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 8.4 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों के लिए यह 5.7 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि महिलाओं को रोजगार के अवसरों में समानता नहीं मिल रही है, और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिक्षा और रोजगार का संबंध

रिपोर्टों के अनुसार, पढ़े-लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के बीच यह दर 12 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। यह स्थिति इस बात को दर्शाती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने में असफल हो रही है।

अनौपचारिक क्षेत्र का दबदबा

भारत में अधिकांश रोजगार अनौपचारिक

क्षेत्र में हैं। केवल 21.7 प्रतिशत लोगों को नियमित वेतन मिलता है, जबकि दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की संख्या 19.8 प्रतिशत है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ये रोजगार जीवन यापन के लिए पर्याप्त हैं?

आर्थिक असमानता

आर्थिक असमानता भी एक बड़ा मुद्दा है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, लेकिन कृषि भी अविकसित है और मौसमी बेरोजगारी का कारण बनती है।

सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े भले ही सकारात्मक दिखें, लेकिन वास्तविकता यह है कि बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे हम अपने युवाओं को रोजगार दे सकते हैं और उन्हें न्यूनतम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर हम इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी बिगड़ सकती है।

नोएडा किसान आंदोलन: जाम में फंसी कई एंबुलेंस, दिनभर राहगीर रहे परेशान; 41 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज

ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर शुक्रवार को प्रदर्शन करने वाले चार नामजद समेत 41 अज्ञात किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीटा-2 कोतवाली में उपनिरीक्षक अंकित यादव ने केस दर्ज कराया है कि शुक्रवार को वह पुलिसबल के साथ शांति व्यवस्था ड्यूटी में एनआरआई कट के पास डयूटी पर मौजूद थे।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर शुक्रवार को प्रदर्शन करने वाले चार नामजद समेत 41 अज्ञात किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीटा-2 कोतवाली में उपनिरीक्षक अंकित यादव ने केस दर्ज कराया है कि शुक्रवार को वह पुलिसबल के साथ शांति व्यवस्था ड्यूटी में एनआरआई कट के पास डयूटी पर मौजूद थे।

इसी दौरान वहां उदल सिंह निवासी सर्फाबाद, अतुल यादव निवासी बहलोलपुर, जयप्रकाश निवासी ग्राम कुंडली, मोहित भाटी निवासी अल्फा-1 व 41 असामाजिक किस्म के व्यक्तियों द्वारा दोपहर करीब 12.50 बजे एनआरआई कट एक्सप्रेसवे रोड पर इकट्ठा होकर दिल्ली पहुंचकर चल रहे संसद सत्र को बाधित करने की बात कह रहे थे, जिनको पुलिस वालों द्वारा समझाया बुझाया गया तो लोग नहीं माने।

उग्र होकर सरकार व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोड को जाम करने का प्रयास करने लगे। एनआरआई कट परी चौक एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो नोएडा-ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। एक्सप्रेसवे के किनारे पर काफी हॉस्पिटल शारदा अस्पताल, जेपी अस्पताल, यथार्थ अस्पताल, जिम्स अस्पताल पड़ते हैं। उग्र प्रदर्शन से यातायात बाधित हो गया।

पुलिस से हुई झड़प

सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। लोगों को पुनः समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सभी लोग और अधिक आक्रोशित होकर नारेबाजी करते हुए रोड को पूर्णतः जाम कर दिया और आक्रोशित होकर देख लेने की धमकी देते हुए पुलिसवालों को गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की करने लगे। जिसमे ऊपर निरीक्षक लाल सिंह, कांस्टेबल विवेक कुमार को चोंट आईं।

जाम में फंसी कई एंबुलेंस

जाम के कारण भीड़ में कई एंबुलेंस फंस गईं। एंबुलेंस को पुलिस ने दूसरे रास्तों से जैसे तैसे निकलवाया। आसपास के रास्ते में आने-जाने वाले लोग भागने लगे, जिससे अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। जैसे-तैसे रास्ता खुलवाया गया और जब यह लोग फिर भी नहीं माने। मनमाने तरीके से शोर मचाते हुए नारेबाजी करते हुए मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचकर मेट्रो ट्रेन रुकवाने का प्रयास किया। अफरा-तफरी के माहौल में कुछ लोग, राहगीरों के जूते-चप्पल भी वहां पर छूट गए, जिनको पुलिस कोतवाली लेकर आई।

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-191 (2) (साधारण दंगा), 121(1) (किसी लोक सेवक को हल्की चोट पहुंचाने), 121(2) (किसी सरकारी कर्मचारी को गंभीर चोट पहुंचाने), 223 (लोक सेवकों द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा), 285 (सार्वजनिक मार्ग पर बाधा पैदा करना), 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला), 221 (लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कामों में बाधा डालने), आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा-7 (अपराध कि उकसाने) की धाराओं में केस दर्ज किया है।

परी चौक जाने वाले मार्ग पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग

किसानों के गिरफ्तारी देने के लिए परी चौक पहुंचने की सूचना से पुलिस शनिवार सुबह से अलर्ट रही। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी स्तर के अधिकारियों ने मौके पर तैनात पीएसी, आरएएफ के जवानों को किसानों को किसी भी हालत में धरना स्थल पर एकत्रित नहीं करने को लेकर निर्देशित किया।

परी चौक जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर चेकिंग की। हालांकि चोरी छिपे परी चौक पर किसान चारपहिया में सवार होकर पहुंचे। इस कारण अल्फा गोल चक्कर से लेकर परी चौक तक ट्रैफिक जाम रहा। प्रदर्शन के चलते यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। प्रदर्शन के दौरान परी चौक के आसपास जाम रहा।

महाकुंभ में दिखेगी नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की झलक, यमुना प्राधिकरण लगाएगा स्टॉल

ग्रेटर नोएडा। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के जरिये देश दुनिया के लोगों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट व फिल्म सिटी की झलक देखने को मिलेगी। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग महाकुंभ में अपनी विकास परियोजनाओं को प्रदर्शित करेंगे। इसमें यमुना प्राधिकरण भी शामिल होगा। प्राधिकरण को स्टॉल के लिए 20 हजार वर्गफीट स्थान आवंटित किया गया है।

बदलते प्रदेश की दिखेगी झलक

प्रयागराज में अगले माह महाकुंभ शुरू होगा। संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए देश दुनिया के लोग प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार महाकुंभ के जरिये बदलते उत्तर प्रदेश की झलक दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने जा रही है। इसके लिए विभागों को महाकुंभ में विकास परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों को स्टॉल के लिए स्थान आवंटित किया गया है।

यमुना प्राधिकरण भी लगाएहा स्टॉल

यमुना प्राधिकरण को भी अरेल रीजन के सेक्टर 23 में बीस हजार वर्ग फीट स्थान स्टॉल लगाने के लिए आवंटित किया गया है। प्राधिकरण के निवेश सेल के नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि महाकुंभ में नोएडा इंटरनेशनल एरपोर्ट, फिल्म सिटी व औद्योगिक परियोजनाओं के माडल प्रदर्शित किए जाएंगे।

परियोजनाओं को दी जाएगी जानकारी

महाकुंभ में आने वालों को इन परियोजनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इसमें बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश व रोजगार सृजन होगा। प्रदेश को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में यमुना प्राधिकरण अहम भूमिका निभाएगा।

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे मिलेगी दवा, काउंटर शुरू

फरीदाबाद। एनआईटी तीन नंबर स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में आने वाले मरीज अब अपनी सुविधा के अनुसार दवा ले सकते हैं। अस्पताल की ओर से 24 घंटे वाला काउंटर शुरू कर दिया गया है। जिसमें मरीज व उसके परिजन कभी भी दवा ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य मरीजों के लिए भी शुक्रवार से चार और नए काउंटर शुरू कर दिए जाएंगे।

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रोजाना करीब 3000 से अधिक मरीज उपचार करवाने के लिए आते हैं। जिसमें फरीदाबाद के अलावा पलवल, होडल, हथीन, पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत, दिल्ली, नोएडा, नूंह आदि जिलों के भी मरीज भी शामिल होते हैं। इन मरीजों को उपचार लेने के बाद दवा के लिए काफी परेशानी होती है। इसी वजह से बृहस्पतिवार से 24 घंटे दवा वाले काउंटर की शुरुआत कर दी गई है। इस काउंटर पर कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर दवा ले सकता है। इस काउंटर का सबसे ज्यादा फायदा मेडिकल कॉलेज के आस पास रहने वाले लोगों को मिलेगा। जो देर रात कभी भी आकर दवा को ले सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल की ओर से शुक्रवार को चार ओर नए काउंटरों को खोल दिया जाएगा। जिसके बाद मरीजों को दवा लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। जिसमें से एक काउंटर दिव्यांग और बुजुर्ग के लिए बनाया जाएगा। जहां पर दिव्यांग और बुजुर्गों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और वह आसानी से दवा उक्त काउंटर से ले सकेंगे।

डीन डॉक्टर अनिल कुमार पांडे का कहना है अब मरीज 24 घंटे अस्पताल में आकर दवा ले सकते हैं। एक काउंटर बृहस्पतिवार से शुरू हो गया है, शुक्रवार से चार और नए काउंटर शुरू किए जा रहे हैं।

यूपी में राष्ट्रीय लोक अदालत के बहिष्कार का अधिवक्ताओं ने किया ऐलान, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलेंगे

गाजियाबाद के वकीलों का विरोध प्रदर्शन 29 अक्टूबर को कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने 14 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके अलावा जिला जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देने का भी निर्णय लिया गया है।

गाजियाबाद। कोर्ट रूम में 29 अक्टूबर को अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में शुक्रवार को भी हड़ताल जारी रही। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में एक बैठक कर अधिवक्ताओं ने 14 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का उत्तर प्रदेश में बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके अलावा जिला जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देने का भी निर्णय लिया गया है।

शुक्रवार को न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार के पास सुबह से ही अधिवक्ताओं का जुटना शुरू हो गया। इस दौरान बागपत, गौतमबुद्धनगर, हापुड़ सहित 22 जिलों के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी पहुंचे।

मंच से अधिवक्ताओं ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जब तक जिला जज का निलंबन नहीं होता है, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी और अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। गाजियाबाद के सभी अधिवक्ता हड़ताल में शामिल होकर एकजुट होकर आंदोलन को तेज बनाएंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के दौरान कोर्ट में अधिवक्ता उपस्थित नहीं होंगे। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के सचिव अमित नेहरा ने कह कि बार काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में मुलाकात कराने का भरोसा दिया है।

गाजियाबाद से अधिवक्ता जिला जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाकर मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भी सौंपेंगे। बार एसोसिएशन के सचिव अमित नेहरा ने शिवम सिंह को पांच वर्ष तक के लिए बार एसोसिएशन की स्थायी सदस्यता से वंचित कर दिया है।

शिवम सिंह पर आरोप है कि उनके पास सीओपी (सर्टिफिकेट आफ प्रेक्टिस) नंबर नहीं है। सीओपी नंबर के बिना कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित होकर प्रेक्टिस नहीं कर सकता।

देवेंद्र फडणवीस भाजपा के लिए चाणक्य बन चमक रहे हैं

फडणवीस का राजनीतिक जीवन अनेक विशेषताओं एवं उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से उसकी शुरुआत की। उनके पिता स्व. गंगाधरराव फडणवीस विधान परिषद सदस्य थे।

महाराष्ट्र में सरकार गठन की राजनीति में दस दिन की सघन वार्ताओं और खासी नाटकीयता के बाद आखिर अंधेरा छंट गया और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति को एक नई दिशा एवं दृष्टि देगा। क्योंकि फडणवीस ने अपने राजनीतिक कौशल से न केवल नये मानक गढ़े हैं बल्कि सकारात्मक राजनीति को नये आयाम दिये हैं। हार का कारण स्वयं को मानने एवं जीत का श्रेय पार्टी एवं सहयोगी दलों को देने की विराट सोच रखने वाले फडणवीस को अब भाजपा के शीर्ष नेताओं में शुमार किया जाने लगा है। फडणवीस ने राजनीति के चाणक्यों के चक्रव्यूहों को कुछ ऐसा भेदा कि लोग उन्हें आधुनिक अभिमन्यु भी कहने लगे। बात सही भी है फडणवीस अब किसी चक्रव्यूह में फंसते नहीं बल्कि उसे भेदकर बाहर निकलते हैं। सामने कोई भी हो शह और मात के खेल में उनकी जीत अब गारंटी बन चुकी है। वे भाजपा के लिए चाणक्य हैं तो विपक्ष के लिए अबूझ पहेली। पिछले एक दशक से महाराष्ट्र की राजनीति उनके ही इर्द-गिर्द घूम रही है। ऐसे कद्दावर राजनेता के नेतृत्व में निश्चित ही अगली पारी सफल होने वाली है। बावजूद इसके विशाल बहुमत वाली इस सरकार के मुखिया के तौर पर फडणवीस की यह पारी किसी भी रूप में कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। फिर भी महाराष्ट्र को राजनीतिक स्थिरता और विकास के नए दौर में ले जाने की जिम्मेदारी निभाते हुए वह हर चुनौती के पार जायेंगे, लोगों ने उनकी पार्टी और सहयोगी दलों पर जो भरोसा जताया है, महायुति सरकार उनकी उम्मीदें पूरी करके एक नये इतिहास का सृजन करेंगी, इसमें कोई शंका दूर तक नजर नहीं आती।

तीसरी बार मुख्यमंत्री का ताज पहनने वाले देवेंद्र फडणवीस ने प्रखर राजनेता, अजातशत्रु, दूरदर्शी नायक एवं महाराष्ट्र-निर्माता के रूप में न केवल देश के लोगों का दिल जीता है, बल्कि विरोधियों के दिल में भी जगह बनाकर, अमिट यादों को जन-जन के हृदय में स्थापित कर अनेक राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किये हैं। फडणवीस यह नाम महाराष्ट्र राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम पृष्ठ है, जिससे एक सशक्त जननायक, स्वप्नदर्शी राजनायक, आदर्श चिन्तक, नये महाराष्ट्र के निर्माता, कुशल प्रशासक के साथ-साथ राजनीति को एक खास रंग देने की महक उठती है। उनके व्यक्तित्व के इतने रूप हैं, इतने आयाम हैं, इतने रंग हैं, इतने दृष्टिकोण हैं, जिनमें वे व्यक्ति और नायक हैं, प्रशासक और राजनेता हैं, प्रबुद्ध और प्रधान है, वक्ता और नेता हैं, शासक एवं लोकतंत्र उन्नायक हैं। महाराष्ट्र राजनीति की एक खास स्थिति जहां सहयोगी दलों की आकांक्षाओं का ध्यान रखने और उन्हें यथासंभव संतुष्ट रखने की जरूरत से जुड़ी चुनौती है वहीं आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति से जुड़े दलों पर बेहतर प्रदर्शन की बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि पहली चुनौती मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को संतोषजनक ढंग से निपटाने की है। एक बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में भाजपा की ताकत को बलशाली बनाने की भी है। इन सब चुनौतियों एवं परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने एवं उनसे पार पाने की क्षमता फडणवीस में दिखती है। जो व्यक्ति 2022 में एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री की बजाय उपमुख्यमंत्री की भूमिका मंजूर कर लेता है, पद से ज्यादा पार्टी हित को सामने रखता है, विशिष्ट परिस्थितियों में पार्टी के आग्रह पर न केवल सरकार का सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है बल्कि चुनाव में पार्टी की अगुआई करते हुए उसे शानदार जीत भी दिलाता है, तो उन्हें मुख्यमंत्री की भूमिका सौंपी जा रही है तो अपनी पात्रता तो वह पहले ही अच्छी तरह सिद्ध कर चुके हैं, अब तो शासन के नये मानक गढ़ने है।

यह स्पष्ट है कि देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक जीवन के नए दौर की शुरुआत संभावनाभरी है। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने अपने भाषण में हिंदवी स्वराज से लेकर अहिल्याबाई होलकर का नाम लेकर अपनी राजनीतिक धारा को बिल्कुल स्पष्ट किया। चुनाव प्रचार के दौरान भी उनकी छवि आत्मविश्वास से भरे हिंदुत्ववादी शुद्ध स्वयंसेवक भाजपा नेता की बनी। उन्होंने कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं और उनको समर्थन देने वाले महाविकास आघाड़ी के विरुद्ध लगातार प्रखर प्रहार से अपनी छवि वर्तमान राजनीतिक धारा के अनुरूप बनाई। चुनाव के समय लगा था कि एक हैं तो सेफ हैं और बंटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर महायुति में मतभेद के बावजूद उन्होंने गजब का संतुलन बनाते हुए इन नारों के बल पर महायुति की जीत को उच्च शिखर देकर सबको आश्चर्यचकित किया। महायुति सरकार की नई पारी पिछली पारी जैसी सहजता और स्थिरता दिखा पाएगी या नहीं यह सवाल तो खड़ा ही है, लेकिन इस सवाल को नकारते हुए नयी सरकार अपना पूरा कार्यकाल उतार-चढ़ाव के बावजूद निष्कंटक पार करेगी। दो पुरानी और सुगठित राजनीतिक पार्टियों में हुई असाधारण तोड़फोड़ के परिणास्वरूप बनी महायुति ने हालांकि 2024 विधानसभा चुनावों में अपनी सार्थकता सिद्ध कर दी है और इसलिए अब इसे किसी भी रूप में कृत्रिम गठबंधन नहीं कहा जा सकता। फिर भी नए मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व को सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने और किसी भी असंतोष से बचने पर खास ध्यान देना होगा।

फडणवीस का राजनीतिक जीवन अनेक विशेषताओं एवं उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से उसकी शुरुआत की। उनके पिता स्व. गंगाधरराव फडणवीस विधान परिषद सदस्य थे। लेकिन इस राजनीतिक विरासत का सहारा लेने के स्थान पर फडणवीस ने अपनी खुद की पहचान बनाई। सामान्य कार्यकर्ता की तरह खुद को तराशा। वे सदा दूसरों से भिन्न रहे, अनूठे रहे। घाल-मेल से दूर। भ्रष्ट राजनीति में बेदाग। विचारों में निडर। टूटते मूल्यों में अडिग। घेरे तोड़कर निकलती भीड़ में मर्यादित। वे भारत के इतिहास में उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने सिर्फ अपने नाम, व्यक्तित्व और करिश्मे के बूते पर न केवल सरकार बनाई बल्कि एक नयी सोच की राजनीति को पनपाया, पारदर्शी एवं सुशासन को सुदृढ़ किया।

2014 में पहली बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस अपनी कल्पनाशीलता, दूरदर्शिता, दृढ़संकल्प, राजनीतिक कौशल एवं अभिनव परियोजनाओं के माध्यम से उन्होंने अपनी असीम क्षमताओं को आकार दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014, 2019 और 2024 के विधानसभा के चुनाव भाजपा ने फडणवीस के नेतृत्व में लड़े और शानदार प्रदर्शन किया, तीनों बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 2019 में उनके नेतृत्व में भाजपा की चुनावी जीत के बावजूद अविभाजित शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे की जिद के कारण वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, हालांकि राकांपा नेता अजित पवार के साथ मिलकर उस वक्त उन्होंने तीन दिन की सरकार जरूर बनाई। यह प्रयोग विफल होने के बाद उनके विरोधियों ने उनकी रणनीतिक क्षमता पर सवाल भी उठाए थे लेकिन देवेंद्र फडणवीस को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था और उन्होंने कहा भी था कि वे पूरे जोश से आयेंगे, तमाम तूफानों के बीच से विजेता की तरह फिर उभरेंगे। ऐसा उन्होंने करके दिखाया। भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने के बावजूद फडणवीस को मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए खासी जद्दोजहद करनी पड़ी है। भाजपा के प्रदर्शन में फडणवीस ने अपने योगदान का पुरजोर दावा किया है। वे चुनाव-प्रचार अभियान के दौरान पार्टी का मुख्य चेहरा थे और उन्होंने राज्य के सभी छह क्षेत्रों में 64 रैलियां कीं। उनको मिली शानदार सफलता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्हें मिला अटूट समर्थन था। संघ इस बात पर अड़ा हुआ था कि भाजपा को कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश की तरह लो-प्रोफाइल नेता नहीं चाहिए और फडणवीस ही इस पद के लिए उसकी पहली पसंद हैं। शाह, योगी और फडणवीस- इन तीनों के सामने अभी बहुत वर्षों की राजनीति शेष है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर बढ़ते हुए फडणवीस को ऐसे सर्वमान्य व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो खींचतान और दबाव के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, उनमें हर बड़ी-से-कड़ी जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता है। इस विधा में उनके कौशल का परीक्षण अब महाराष्ट्र में तीन-पक्षीय गठबंधन सरकार के नेतृत्व से होने जा रहा है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर

गैस कार इंजन की तुलना में ईवी व्हीकल में बैटरियों को सस्ते में जा सकता है बदला

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बदलने की लागत पारंपरिक दहन इंजन कार इंजन की लागत से कहीं अधिक है। हालांकि, विशेषज्ञों का अनुमान है कि दशक के अंत तक इसमें बदलाव हो सकता है और ईवी बैटरियां संभावित रूप से सस्ती हो जाएंगी।

ईवी बैटरियों की कीमत $20,000 तक हो सकती है। पारंपरिक इंजन को बदलने में आमतौर पर अधिकतम $10,000 का खर्च आता है।

इलेक्ट्रिक वाहन प्रतिस्थापन प्रदाता रिक रेंट का अनुमान है कि 2030 तक एक बड़े ईवी बैटरी पैक की कीमत लगभग $5,000 हो सकती है। अधिक मानक मॉडल के लिए केवल $3,375 की आवश्यकता हो सकती है। यह 2020 में बैटरी बदलने की लागत का केवल 30% है।

उद्योग वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले वर्षों में प्रमुख बैटरी घटकों की लागत कम हो जाएगी, जिससे नए ईवी बैटरी उपकरणों की लागत कम हो सकती है।

बैटरी की कम लागत से इस्तेमाल की गई ईवी को खरीदना आसान हो सकता है और इस्तेमाल की गई कार बाजार पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

इस्तेमाल की गई ईवी की औसत कीमत लगभग $25,000 है, लेकिन उस कुल कीमत में $20,000 की बैटरी जोड़ने की संभावना का मतलब है कि नई कार की दुकान भी बहुत महंगी हो सकती है। बैटरी बदलने की लागत कम होने के कारण, इस्तेमाल की गई ईवी स्टॉक की गई बैटरी भविष्य में शुरू में बहुत अधिक लागत के साथ नहीं आ सकती है।

GETTING A NEW EV BATTERY COULD BECOME CHEAPER THAN REPLACING A GAS CAR ENGINE

GETTING A NEW EV BATTERY COULD BECOME CHEAPER THAN REPLACING A GAS CAR ENGINE

एएसएल मोटर्स ने ईवी के साथ मनाया ग्रीन डे, दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

परिवहन विशेष न्यूज

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, जमशेदपुर स्थित एएसएल मोटर्स ने शनिवार, 07 दिसंबर को ईवी के साथ ग्रीन डे मनाया। यह कार्यक्रम मस्ती, रचनात्मकता और ग्रीन मोबिलिटी के भविष्य को अपनाने के प्रति जागरूकता से भरपूर रहा। इस दौरान ड्राइंग प्रतियोगिता, ग्राहकों के लिए मुफ्त मेहंदी सेवा और अन्य मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन किया गया।

टेस्ट ड्राइव लेने वाले सभी ग्राहकों को उपहार दिए गए। यह विशेष ऑफर पूरे महीने के लिए वैध है और टेस्ट ड्राइव लेने वाले प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित उपहार मिलेगा। यह कार्यक्रम ग्रीन भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्राहक मौजूद थे।

सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशन पर सभी प्रकार के वाहन होंगे चार्ज

परिवहन विशेष न्यूज

इंदौर में शुक्रवार 06 दिसंबर से शहरवासियों को फास्ट व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की सौगात मिल गई है। दोपहर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक मालिनी गौड़ ने विश्राम बाग के पास आम जनता के लिए संचालित वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया।

एआईसिटीएसएल द्वारा पीपीपी मोड पर संचालित अक्षय ऊर्जा पर आधारित सोलर बेस फास्ट चार्जिंग स्टेशन के जरिए दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। दो चार्जर के जरिए एक बार में पांच वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा।

फास्ट चार्जिंग के लिए वाहन चालक को 18 रुपए और स्लो चार्जिंग के लिए 15 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे। इसके साथ ही बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी होगा, जिसमें कुल 8 बैटरियां होंगी। वाहन द्वारा हर मिनट के अंतराल पर बैटरी को बदला और रिफिल किया जा सकेगा। यह चार्जिंग स्टेशन सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन में कुल 8 बैटरियां हैं। स्टेशन का संचालन जीवाह इंटरनेशनल द्वारा किया जाएगा।

दिल्ली कॉमिक कॉन में यामाहा का धमाका: स्टाइल, स्पीड और रोमांच का शानदार मेल!

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के एनएसआईसी ग्राउंड्स ओखला में कॉमिक कॉन का आयोजन किया गया। यहां पर पॉप कल्चर और ब्लू थीम वाले यामाहा एक्सपीरियेंस जोन का दिलचस्प संगम देखने के लिये उत्सुक दिखाई दिए। समुराई थीम का MT-03 उनका पसंदीदा फोटो स्पॉट बन गया जबकि YZF-R15 ने लीन एंगल पर पोजिंग का अनूठा अनुभव दिया। एक प्रीमियम और स्पोर्टी ब्रैंड के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया।

नई दिल्ली। इंडिया यामाहा ने दिल्ली कॉमिक कॉन के अनुभव को यादगार बना दिया। यह आयोजन 6 से 8 दिसंबर को एनएसआईसी ग्राउंड्स, ओखला, नई दिल्ली में हुआ। इसमें हजारों उत्साही लोग, इंफ्लूएंसर्स, कॉमिक बुक्स के प्रेमी, एनिमे के फैंस और मोटरसाइकलों के शौकीन आये थे। वे सभी पॉप कल्चर और ब्लू थीम वाले यामाहा एक्सपीरियेंस जोन का दिलचस्प संगम देखने के लिये उत्सुक थे।

यामाहा ने लगाया मोटोजीपी गेमिंग सेटअप

यामाहा एक्सपीरियेंस ज़ोन इस उत्सव का मुख्य आकर्षण था, जिसमें ऐसी कई गतिविधियाँ हुईं, जिन्होंने आने वाले लोगों को रोमांचित कर दिया। आने वाले लोगों ने मोटोजीपी गेमिंग सेटअप का मजा लिया और वर्चुअल रेसिंग के रोमांच में खो गये। समुराई थीम का MT-03 उनका पसंदीदा फोटो स्पॉट बन गया, जबकि YZF-R15 ने लीन एंगल पर पोजिंग का अनूठा अनुभव दिया। इसमें रेसट्रैक कॉर्नर के जैसी भागमभाग थी।

इंस्टैन्ट फोटो शेयरिंग की सुविधा

RayZR स्ट्रीट रैली ने रोमांच को बढ़ाते हुए इंस्टैन्ट फोटो शेयरिंग की सुविधा दी और प्रशंसकों ने अपनी पसंदीदा यादों को संजो लिया। आने वाले लोगों ने मोटरसाइकलिंग में गहरी रुचि दिखाई और बताया कि वे यामाहा को कितना चाहते हैं। इसके बदले में कंपनी ने सबसे ज्यादा रुचि दिखाने वाले कॉमिक्स तथा मोटरसाइकलिंग के शौकीनों को कॉमिक कॉन सुपर फैन बॉक्स और यामाहा की खास कॉमिक कॉन थीम वाली मर्चेंडाइज तथा यामाहा गुडीज दीं।

प्रीमियम और स्पोर्टी ब्रैंड

यामाहा ने दिल्ली कॉमिक कॉन में अपनी भागीदारी से भारत के युवाओं के लिये अभिनव एवं दिलचस्प अनुभव देने की प्रतिबद्धता दिखाई है। इसने एक प्रीमियम और स्पोर्टी ब्रैंड के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। कंपनी भारत के दूसरे शहरों में आगामी कॉमिक कॉन इवेंट्स के लिये भी तैयार है।

महिंद्रा ने ईवी 'बीई 6ई' का ब्रांड नाम बदलकर 'बीई 6' किया, कहा ट्रेडमार्क के लिए मजबूती से लड़ेंगे

महिंद्रा ने ईवी 'बीई 6ई' का ब्रांड नाम बदलकर 'बीई 6' किया, कहा ट्रेडमार्क के लिए मजबूती से लड़ेंगे

परिवहन विशेष न्यूज

कंपनी ने शनिवार, 07 अक्टूबर को कहा कि उसने अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड का नाम बदलकर 'बीई 6' करने का फैसला किया है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह ट्रेडमार्क 'बीई 6ई' के लिए इंटरग्लोब एविएशन के साथ अदालत में मजबूती से लड़ाई जारी रखेगी।

एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के मालिक इंटरग्लोब एविएशन ने अपने नए ईवी ब्रांड में 6ई के इस्तेमाल को लेकर एमएंडएम को अदालत में घसीटा है।

एमएंडएम ने एक बयान में कहा, "हमें यह अनुचित लगता है कि दो बड़ी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक विचलित करने वाले और अनावश्यक संघर्ष में शामिल हैं, जबकि वास्तव में हमें एक-दूसरे के विकास और विस्तार का समर्थन करना चाहिए।"

बयान में आगे कहा गया है कि इसलिए कंपनी अपने उत्पाद को 'बीई 6' के रूप में ब्रांड करने का फैसला कर रही है। एमएंडएम ने कहा, "हालांकि, हमारा मानना है कि इंडिगो का दावा निराधार है और अगर इसे चुनौती नहीं दी गई तो यह अल्फाबेटिक-न्यूमेरिक 2-अक्षर चिह्नों पर एकाधिकार करने की अनावश्यक मिसाल कायम करेगा, जबकि हमारा चिह्न विशिष्ट और अलग है। यह सभी उद्योगों और क्षेत्रों की सभी कंपनियों के लिए एक बड़ी बाधा होगी।"

कंपनी ने कहा कि वह अदालत में इसका पुरजोर विरोध करती रहेगी और बीई 6ई ब्रांड नाम पर अपना अधिकार सुरक्षित रखेगी।

टायरों पर बने अलग-अलग पैटर्न का क्या होता है मतलब, वाहनों के लिए कितने होते हैं जरूरी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आपने ट्रैक्टर, कार, बाइक, साइकिल में लगे हुए टायरों को देखा होगा। इन टायरों के ऊपर बने हुए अलग-अलग डिजाइन भी देखे होंगे। इन डिजाइनों को ट्रेडमार्क कहा जाता है। यह किसी भी वाहन को सही से चलाने में अहम भूमिका निभाती है। इन ट्रेड की वजह से वाहन कीचड़, रेतिली और ऑफ रोड जैसी जगहों पर आसानी से चल पाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि यह पैटर्न होते क्या हैं और उन्हें अलग-अलग क्यों बनाया जाता है।

क्या है टायर ट्रेड?

टायर ट्रेड टायर पर लगे हुए ट्रैड होते हैं, जो सड़क की सतह के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। टायर का संपर्क क्षेत्र जितना बड़ा होगा, टायर की पकड़ उतनी ही अधिक होती है। वहीं, आपने देखा होगा कि रेसिंग गाड़ियों की टायरों में किसी तरह का कोई ट्रेडमार्क नहीं होता है, जो पूरे सतह क्षेत्र को जमीन के संपर्क में रहने देता है। जिसकी वजह से उनकों सड़क पर ज्यादा पकड़ बनी रहती है। इन्हें स्लिक टायर कहा जाता है, लेकिन यह टायर आम सड़कों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह गीली सतहों पर नहीं चल सकती है।

टायर के ट्रेड पार्ट्स

टायर के ट्रेड में आपको रबर की कई परते देखने के लिए मिलेंगी। ये ट्रेड अलग-अलग आकार और डिजाइन के होते हैं। जिनका अपना-अपना काम होता है। आइए जानते हैं कि किसका क्या मतलब है।

ब्लॉक

टायर पर बने हुए उभरे हुए पार्ट्स को ब्लॉक कहा जाता है। यह खांचे से अलग होत हैं। यह अपने साइज और साइज के आधार पर टायर को सड़क पर पकड़ बनाए रखने में मदद करते है। इन्हें ट्रेड ब्लॉक को लग्स भी कहा जाता है।

रिब

रिब टायर का वह हिस्सा होता है, जो टायर की परिधि के साथ ही चलता है। यह शोर को कम करने में मदद करता है। रिब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ब्रेकिंग के दौरान कर्षण प्रदान करने के लिए होता है। साथ ही मोड़ के समय यह टायर की पकड़ सड़क पर बनाकर रखता है।

साइप्स

यह बारिश के मौसम या फिर सड़क पर लगे पानी को सतह से हटाने का काम करता है। साथ ही यह हाइड्रोप्लानिंग को रोकने में भी मदद करता है। यह पैटर्न और स्थिति को एक्स्ट्रा काटने वाले किनारे बनाकर अधिक कर्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है।

ग्रूव

टायर में दिखाई देने वाले खांचे बने हुए दिखाई देते हैं, उन्हें ही ग्रूव कहा जाता है। यह टायर की सतह के नीचे से पानी को किनारों की तरफ ले जाने का काम करते हैं। जिससे हाइड्रोप्लेनिंग को रोका जा सकता है। यह हवा को ट्रेड ब्लॉक से गुजरने में भी मदद करते हैं। साथ ही टायर को ठंडा होने में मदद करते हैं।

जनवरी से बढ़ जाएंगी वाहनों की कीमतें

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। कई कार निर्माताओं ने 1 जनवरी 2025 से अपने पोर्टफोलियो में मूल्य वृद्धि की घोषणा की है। मूल्य संशोधन के लिए प्रमुख कारण वस्तुओं और परिचालन लागत में वृद्धि बताया गया है।

हुंडई इंडिया ने अपनी सभी कारों की कीमतों में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। कोरियाई ब्रांड के पास हमारे बाजार में वेन्यू, क्रेटा और एक्सटर जैसी कई कारें और एसयूवी हैं, साथ ही आयोनिक 5 ईवी जैसे हाई-एंड मॉडल भी हैं। ब्रांड अगले महीने क्रेटा ईवी से पर्दा उठाएगा।

निसान हाल ही में फेसलिफ्ट की गई मैग्नाइट एसयूवी की कीमतों में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी। मैग्नाइट निसान की एकमात्र मेड-इन-इंडिया एसयूवी है जिसे घरेलू स्तर पर बेचा जाता है और साथ ही विदेशों में कई देशों में निर्यात किया जाता है। हालांकि, कंपनी ने फ्लैगशिप एक्स-ट्रेल एसयूवी के लिए बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है।

ऑडी इंडिया ने 1 जनवरी, 2025 से अपनी कारों और एसयूवी की कीमतों में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। भारत में ऑडी की स्थानीय रूप से असेंबल की गई रेंज में A4 और A6 सेडान के साथ-साथ Q3, Q3 स्पोर्टबैक, Q5 और Q7 एसयूवी शामिल हैं।

ब्रांड भारतीय बाजार में A5 स्पोर्टबैक, Q8 एसयूवी और इसके इलेक्ट्रिक डेरिवेटिव और ई-ट्रॉन जीटी और RS ई-ट्रॉन जीटी जैसे आयातित उत्पाद भी बेचता है।

बीएमडब्लू इंडिया ने भी अपने पोर्टफोलियो में 3 प्रतिशत तक की कीमत वृद्धि की घोषणा की है। बीएमडब्लू 2 सीरीज ग्रैन कूप, 3 सीरीज ग्रैन लिमोसिन और M340i, 5 सीरीज LWB, 7 सीरीज, X1, X3, X5 और X7 SUV को स्थानीय रूप से असेंबल किए गए मॉडल के रूप में बेचती है। इस बीच, बीएमडब्लू के आयातित मॉडल में i4, i5 और i7 इलेक्ट्रिक कार, iX1 और iX इलेक्ट्रिक SUV, Z4, M2 कूप, M4 कॉम्पिटिशन और CS, M8, XM और हाल ही में लॉन्च की गई M5 शामिल हैं।

मर्सिडीज बेंज इंडिया इस साल के अंत में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा करने वाली पहली कार निर्माता कंपनी थी। इसके मॉडलों की कीमतें 3 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। मर्सिडीज ने स्पष्ट किया है कि GLC की कीमतें 2 लाख रुपये तक बढ़ जाएंगी जबकि मर्सिडीज-मेबैक S680 V12 की कीमत 9 लाख रुपये अधिक होगी। इसके अलावा, 31 दिसंबर, 2024 तक निर्मित होने वाले मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी, जिसमें इस तिथि से पहले बुक की गई इकाइयाँ भी शामिल हैं।

बढ़ता मृदा प्रदूषण, घटता उत्पादन

विजय गर्ग

मिट्टी के ऊपर भुरभुरा और स्नेहिल तत्त्व बीजों को अंकुरित कर और जड़ों को धारण कर हमारी धरती पर जीवन सुनिश्चित करता है। यह आज के दौर में आठ अरब लोगों के लिए खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित के करने, बिगड़ते पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और जलवायु संकट को काफी हद तक कम करने का मजबूत संबल है। मगर आज प्राणियों के लिए पोषक मिट्टी का अस्तित्व खुद गंभीर संकट में घिरा है। मिट्टी का बड़े पैमाने पर क्षरण न केवल कृषि पैदावार और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को और अधिक व्यापक तथा जटिल बना रहा है। मिट्टी के क्षरण के साथ उसकी उत्पादकता की कमी धीरे-धीरे बढ़ रही है, प्रदूषण के इतर इसका दायरा आधुनिक कृषि तरीकों के कारण दबे पांव फैल रहा है।

मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, जमा होता नमक और जहरीले रसायनों के संदूषण और फसल उत्पादन में आ रही कमी मृदा क्षरण के दायरे आते हैं। मृदा क्षरण आमतौर पर मौजूदा रसायनों (जिसमें खाद और जहरीले कीटनाशक शामिल हैं) के अंधाधुंध इस्तेमाल, भूमि के परंपरागत उपयोग में व्यापक बदलाव, जंगल की कटाई, बाढ़, सुखाड़, जलजमाव और जलवायु परिवर्तन से । तापमान आदि कारणों से पैदा होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां खेती-किसानी आज भी अधिकांश लोगों के लिए जीविका का स्रोत है, दस लाख 78 हजार वर्ग किलोमीटर दायरे में फैले विश्व के दूसरे सबसे बड़े कृषि तंत्र की रीढ़ मिट्टी ही है। मृदा क्षरण का गहराता संकट न सिर्फ पैदावार को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में यह अनेक समस्याओं का कारण बन रहा है, जिनमें मुख्य रूप से पारिस्थितिकी असंतुलन भी शामिल है। मिट्टी सर्वेक्षण के राष्ट्रीय ब्यूरो के मुताबिक भारत में लगभग एक तिहाई मिट्टी के यानी लगभग 12 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र मृदा क्षरण के दायरे में है, जिसका अच्छा-खासा हिस्सा समुद्र के लवणीकरण से प्रभावित है। बड़े पैमाने पर मृदा क्षरण के बावजूद, तकनीक आधारित गहन कृषि कारण पैदावार में वृद्धि हुई और अब भारत कृषि उपज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वह खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। मगर बाढ़ के दौरान और निर्माण कार्य के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी के कटाव, रासायनिक खाद के व्यापक इस्तेमाल से जमा होती लवणता, बढ़ती अम्लीयता और जलभराव आदि से कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग ऊसर होता जा रहा है। अगर इसी तरह मृदा क्षरण जारी रहा तो आने वाले वर्षों में खाद्य आयात करना पड़ सकता है, जबकि भारत, दुनिया के केवल 2.4 फीसद भूमि क्षेत्र के साथ, विश्व की 18 फीसद आबादी को खिलाने में सक्षम है।

मृदा क्षरण के प्रमुख कारणों में अमर्यादित तरीके से खेती के अलावा बड़े पैमाने पर शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए भूमि उपयोग में व्यापक बदलाव भी जिम्मेदार है। इसके साथ-साथ भारत मवेशियों की संख्या के लिहाज से भी सबसे बड़ा देश है। इनके चरने के दौरान जमीन की ऊपरी वनस्पति हटने से मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और यह वर्षा और हवा के कारण कटाव का शिकार हो जाती है। भारत जनसंख्या के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा देश है और डेढ़ अरब लोगों का पेट भरने के लिए जरूरी अनाज उत्पादन का दबाव कृषि पर लगातार बना हुआ है। साथ ही उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा रखरखाव और अक्षम प्रबंधन के कारण बर्बाद हो जाता है। इन सबका असर अंततः मिट्टी पर पड़ता है।

आजादी के बाद अनाज की बढ़ती जरूरत और खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति का प्रकल्प लागू हुआ, जो मुख्य रूप से कृत्रिम सिंचाई, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक और संकर बीज पर आधारित था, जिसका मुख्य लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन इस प्रयास में मिट्टी की उर्वरता नेपथ्य में चली गई। लगातार एक ही तरह की फसल उगा कर ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा किया जाने लगा, जिससे मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्त्व कम होने लगे। इसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव और जैविक पदार्थ खत्म होते चले गए। वर्तमान में कृषि कार्य में 94 फीसद तक रसायनिक उर्वरक का उपयोग होता है। यहां तक कि रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से हमारे खेतों और फसलों को जहरीला बना दिया। हरित क्रांति के दौरान हमारा अनाज उत्पादन पांच करोड़ टन से बढ़ कर तीस करोड़ टन पहुंच गया, पर यह उपलब्धि उपजाऊ मिट्टी की कीमत पर हासिल की गई प्रतीत होती है। ऐसे में मिट्टी का तेज गति से क्षरण भारत की बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा के गंभीर संकट का कारण बन सकता है। मृदा क्षरण के कारण न सिर्फ उत्पादकता में कमी आती है, बल्कि इसमें प्राकृतिक रूप से मौजूद कार्बन की मात्रा कम हो जाने से इसकी पानी सोखने और जकड़ कर रखने की क्षमता भी काफी हद तक घट जाती है। नतीजा यह कि पानी के स्रोतों से जल का पुनर्भरण काफी कम हो जाता है, जो भारत में बड़े स्तर के भूजल स्तर में गिरावट और सूखे की बढ़ रही समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। हरियाणा और पंजाब, जो भारत के सबसे अधिक अनाज उत्पादक हैं, वहां जल स्तर खरतनाक रूप से गिर चुका है। । समृद्ध और उपजाऊ मिट्टी कृषि प्रधान भारत के लिए वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखती है। तभी तो पिछले कुछ दशक में आई बड़े स्तर की वैश्विक मंदी में भी भारतीय अर्थव्यस्था मामूली असर के साथ तेजी से आगे बढ़ती रही।

उर्वर मिट्टी आज के दौर में भारत जैसे देश के लिए न सिर्फ पेट भरने किए जरूरी, बल्कि अर्थव्यवस्था की धुरी है। ऐसे में जरूरत है कि मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक तरीके से वापस लाया जाए। इसके लिए हमें मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक स्वास्थ्य को बहाल करने की आवश्यकता होगी, जो एक लंबी और जटिल, पर संभव प्रक्रिया है। अपने जैविक तत्त्व यानी कार्बन को खोकर ऊसर हो चुकी मिट्टी में दोबारा जैविकता लौटाने की जरूरत होगी। अभी कुल इस्तेमाल हो रहे उर्वरकों में केवल छह फीसद जैविक स्रोत वाले उर्वरक का इस्तेमाल हो है। जरूरत । है कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम कर जैविक खाद आधारित खेती-किसानी को प्रोत्साहन मिले। हालांकि इससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी की आशंका शामिल है।

भारत में। प्रकृति केंद्रित समृद्ध कृषि परंपरा रही है, जो मिट्टी की क्षमता, मौसम और पानी की उपलब्धता के सामंजस्य पर आधारित है। इसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। दबे पांव मिट्टी पानी का संकट हमारे खेतों से होते हुए हमारी थाली तक आ पहुंचा है। ऐसे में इस भीषण समस्या का संज्ञान लेने और सरकार, समाज तथा व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है।

दिल्ली-एनसीआर के लोग आखिर कहां जाएं

सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के लगातार प्रयासों के बावजूद प्रदूषण से बिगड़े हालात में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। दरअसल नौकरशाह नेताओं के इशारों पर काम करते हैं। नेता वोट के कारण किसानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से कतराते हैं'

देश की राजधानी दिल्ली का प्रदूषण इतना खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली आने से घबराते हैं। गडकरी ने कहा कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडने से वह दिल्ली आने से कतराते हैं। गडकरी मंत्री हैं। उनके पास साधन और सुविधाएं हैं। वह कहीं भी आसानी से आवागमन कर सकते हैं। सवाल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र (एनसीआर) के करोड़ों लोगों के जीवन का है। इतने लोग अपना कामकाज, घर-बार छोड़ कर कहां जाएं। प्रदूषण के धीमे जहर को पीना उनकी मजबूरी बन गई है। ज्यादातर सांसदों, मंत्रियों पर अकूत दौलत है। उनके लिए प्रदूषण से बचने के लिए कहीं भी देश में सरकारी खर्च पर आना-जाना आसान है। वैसे भी नेताओं को संसद और विधानसभा को सुचारू चलाने की ज्यादा चिंता नहीं है। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को सरकारी मशीनरी और नेताओं के नकारापन का अभिशाप झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली हर तरह के जानलेवा प्रदूषण की शिकार है। वाहनों और फैक्टरी के धुएं से होने वाला प्रदूषण, यमुना का प्रदूषण और घरों-प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे का प्रदूषण। तीनों तरह के प्रदूषण का बोझ उठाने के लिए दिल्ली अभिशप्त हो चुकी है। दिल्ली में केंद्र में भाजपा गठबंधन की और राज्य में आप की सरकार मौजूद हैं। इससे पहले दिल्ली में लंबी अवधि तक कांग्रेस का शासन रहा है। प्रदूषण से निपटने में सभी राजनीतिक दल नाकाम रहे हैं। दिल्ली में कचरे का पहाड़ आज भी नेताओं के दावों-वादों को मुंह चिढ़ा रहा है।

हिंदू-मुस्लिम विवाद और भ्रष्टाचार की तरह प्रदूषण नेताओं के लिए कभी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। जब कभी प्रदूषण का मुद्दा उठता भी है, तो केंद्र और दिल्ली की सरकार गेंद एक-दूसरे के पाले में डाल कर अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाती हैं। यही वजह है कि दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा इतनी बिगड़ चुकी है कि सांस लेना भी दूभर हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले कम से कम 10 सिगरेट जितना प्रदूषण हर दिन लेने को विवश हैं। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जैसी संवैधानिक स्वतंत्र संस्थाएं भी तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण से निपटने में प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर सकीं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अपने बयान में स्वीकार किया था कि दिल्ली में 50 प्रतिशत प्रदूषण वाहनों से निकलता है। गडकरी देश के परिवहन मंत्री हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर प्रदूषण की विकराल समस्या से निपटने की जिम्मेदार किसकी है। जब देश का परिवहन मंत्री ही समस्या के समाधान से मुंह चुराने लगे तो अवाम किससे उम्मीद करे। स्विस संगठन की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दिल्ली को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला राजधानी शहर बताया गया है। रिपोर्ट 2023 के अनुसार, 2023 में 134 देशों में से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत की वायु गुणवत्ता तीसरी सबसे खराब की भविष्यवाणी की गई। राष्ट्रीय राजधानी को वर्ष 2018 से लगातार चार बार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि अनुमान है कि भारत में 1.36 अरब लोग पीएम 2.5 की सांद्रता का अनुभव करते हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुशंसित वार्षिक दिशानिर्देश स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण से खराब हालात में सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रयास भी सरकारों के नकारापन के कारण बौने साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट दर्जनों बार फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अदालत ने कहा कि सरकारी एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय की कमी है। साथ ही अदालत ने कहा कि दिल्ली में फिलहाल ग्रैप-4 जारी रहेगा। दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीपीसीसी, सीएक्यूएम और अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय की पूरी तरह से कमी है। समन्वय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पर है।

इसलिए ग्रैप-4 को लागू करने के लिए समन्वय हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को फटकार लगाई क्योंकि राज्य प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने में विफल रहे। यह ऐसे समय में हुआ है जब दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब बनी हुई है, जिससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मामले की सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत की पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा खेतों में लगी आग को बुझाने के प्रयासों को मात्र दिखावा करार दिया। हवा की गुणवत्ता खराब होने का एक स्पष्ट कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में पराली जलाने की बार-बार होने वाली घटनाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर को पर्यावरण कानूनों को शक्तिहीन बनाने के लिए केंद्र की आलोचना की और कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अधिनियम के तहत पराली जलाने पर दंड से संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के प्रावधान को लागू करने के लिए कोई आवश्यक तंत्र बनाए बिना ही अधिनियम लागू कर दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारत में हर साल पैदा होने वाले 22 मिलियन टन चावल के ठूंठ में से लगभग 14 मिलियन टन पराली को आग के हवाले कर दिया जाता है। यह पैदा होने वाले चावल के ठूंठ का लगभग 63.6 प्रतिशत है और हरियाणा और पंजाब में अकेले जलाई जाने वाली पराली का 48 प्रतिशत हिस्सा है। हालत यह है कि वोटों के डर से राज्य और केंद्र की सरकारें पराली जलाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगा पा रही हैं। राजनीतिक दलों के लिए किसानों का वोट बैंक आम लोगों के जीवन पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि पराली जलाने की हर साल होने वाली घटनाओं के बावजूद कोई भी सरकार सख्त कदम उठाने से हिचकिचाती है। यहां तक कि सरकारें वोटों के लालच में लगातार अदालत के निर्देशों की अवहेलना कर रही हैं।

कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने कथित तौर पर कैथल जिले में पराली जलाने के आरोप में 18 किसानों को गिरफ्तार किया था। ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने में विफल रहने के कारण राज्य के कृषि विभाग के करीब 24 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था। गौरतलब है कि हजारों किसान पराली हर साल जलाते हैं। इसके बावजूद कुछ किसानों की गिरफ्तारी महज दिखावा है। केंद्र सरकार ने 2022 में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर राज्यों में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना शुरू की। पंजाब को पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए 2018-22 के दौरान इस योजना के तहत 1387.6 करोड़ रुपए से अधिक मिले। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 22 अक्टूबर को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह बताए कि राज्य में धान की पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के लगातार प्रयासों के बावजूद प्रदूषण से बिगड़े हालात में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। दरअसल नौकरशाह नेताओं के इशारों पर काम करते हैं। नेता वोट के कारण किसानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से कतराते हैं। यह निश्चित है कि विश्व में प्रदूषण को लेकर बदनाम हो चुकी राजधानी के हालात सुधारने के लिए जब तक अदालतें नौकरशाहों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करेंगी, तब तक इनकी प्रवृत्ति में सुधार संभव नहीं है। दिल्ली की गंदी होती सांसों को स्वच्छ बनाने की जरूरत है।

प्रदूषण से बढ़ता कैंसर का जोखिम

विजय गर्ग

भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में 22 प्रतिशत हिस्सा कैंसर का है। हाल ही में 'द लांसेट' में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि यह आंकड़ा पिछले एक दशक में दोगुना हो गया है। विशेष चिंता की बात यह कि इनमें युवा आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है। कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि के कई बड़े कारण हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जीवनशैली में बदलाव मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वर्तमान में कैंसर का एक प्रमुख कारण प्रदूषण भी है। वस्तुतः आज वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण अपने चरम पर है जिसकी वजह से कैंसर रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के कारण बढ़ते कैंसर के मामलों ने चिकित्सा जगत में चिंता पैदा कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली लगातार तीसरे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, जहां पी. एम. 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 20 गुना अधिक है। ये आंकड़े करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी एक भयावह वास्तविकता हैं। कैंसर विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिनमें से 37 प्रतिशत मरीज ऐसे हैं जो कभी धूमपान नहीं करते थे। एम्स द्वारा वर्ष 2023 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में प्रतिवर्ष लगभग 80 हजार लोग वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से प्रभावित होते हैं।

वस्तुतः पराली दहन उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के एक नए कारक के रूप में उभर कर सामने आया है। एम्स और आइआइटी दिल्ली द्वारा 2023 में किए गए एक संयुक्त अध्ययन में यह पाया गया कि पराली के धुएं में बेंजीन, फार्मल्डिहाइड और पालीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कैंसरकारी तत्व मौजूद होते हैं। इन तत्वों की मात्रा सामान्य दिनों की तुलना में पराली जलाने के मौसम में छह गुना तक बढ़ जाती है।

वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए कैंसर के कारकों का समाधान किए जाने पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में सरकार को पराली से होने वाले वायु प्रदूषण के कारकों के निवारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि उससे उत्पन्न कैंसर की भयावहता को रोका जा सके।

हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, ग्रीन कवर में वृद्धि और औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी निगरानी आदि इनमें शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर, वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, शराब और तंबाकू से परहेज और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर कैंसर के मामलों से बचा जा सकता है।

• जिंदगी के मोड़

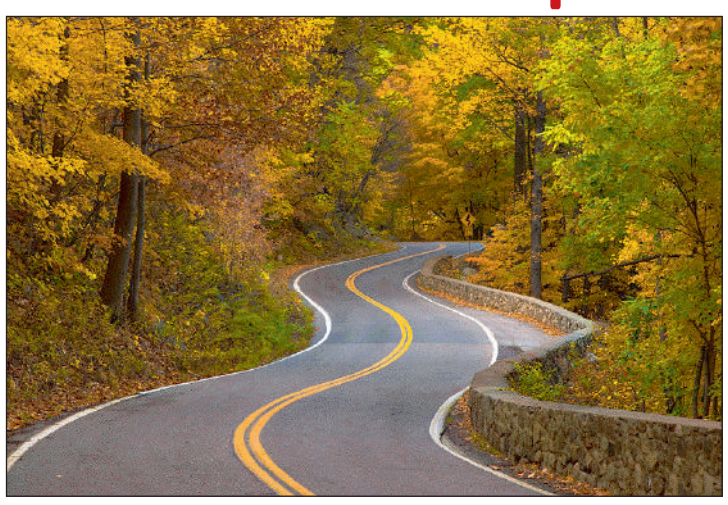

जिंदगी के रास्तों पर अनेक जगह चाहे- अनचाहे मोड़ आ जाते हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता। किसी भी रास्ते पर सही जगह मुड़ने का खास महत्त्व है। वाहन चलाते हुए भी कई बार ऐसा हो जाता है। कि हम रास्ता भूल जाते हैं, सड़क पर आगे निकल जाते हैं और एकदम से बाएं या दाएं नहीं मुड़ सकते। हमें कुछ आगे जाकर वापस मुड़ने के लिए बनाई गई जगह या 'यूटर्न' से पीछे आना पड़ता है और सही रास्ता लेना होता है। खासकर लंबी दूरी की सड़कों पर कहीं भी मुड़ जाने की सुविधा हर कहीं नहीं होती। इस क्रम में कई बार काफी दूरी का सफर तय करना पड़ता 1 अपनी मर्जी से कहीं भी मुड़ जाने पर तेज रफ्तार सड़कों पर जोखिम से गुजरना या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है। जिंदगी एक दिलचस्प, अप्रत्याशित घटनाओं और संभावनाओं से भरा सफर है। इसे सुरक्षित तरीके से तय करते रहने वाले भी अनेक बार गलती से आगे, इधर या उधर चले जाने के कारण थोड़ा पीछे आते हैं और फिर सही रास्ता अपना लेते हैं, ताकि आगे बढ़ते रहें। यों भी, सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अगर थोड़ी दूरी भी तय करनी पड़े, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बल्कि यह अपने हित में होता है।

इस सफर में उचित स्थिति अपने मन की बात कहकर यह आकलन कर लेने की है कि आपके शब्द सामने वाले को बुरे तो नहीं लगे या कितने बुरे लगे । अगर माफी मांगना जरूरी है, तो वक्त की जरूरत के मुताबिक माफी मांग भी लेनी चाहिए। खुले दिल से माफी मांग ली जाए। संबंधों का पुल सलामत रहता है । जमाने से सुनते आए हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन जबान से निकले शब्दों से बना जख्म कभी नहीं भरता। हालांकि वक्त के साथ यह बात अपनी प्रवृत्ति बदल रही है । तो शब्द उन फलों की तरह हैं कि पहले भेंट कर दें, पता चले कि सामने वाले ने चख लिए, लेकिन स्वाद नहीं लगे तो फल वापस ले लिए जाएं। शब्दों में अब वह पुरानी बात नहीं रही। जिंदगी बाजार की गिरफ्त में है । कहे गए शब्द वापस लिए जा सकते हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह से सामने वाले को भी बेहतर लगने लगेगा । जिंदगी जीने के अंदाज सिखाने वाले कम नहीं हैं। राजनीति भी अब जिंदगी की प्रशिक्षक हो गई है। यह सिखाती है कि बात कैसे करते हैं । अवसर और परिस्थिति के अनुसार कौन-से स्वादिष्ट या बेस्वाद शब्द दूसरों को परोसने चाहिए । यह अभिनेताओं को अभिनय सिखा रही है। उन्हें समझाती है कि राजनीति में सिर्फ अभिनय नहीं करते, बल्कि बहुत समझदारी भरी कुटिलता से अभिनय करते हैं । काबिल अभिनेता भी अगर वांछित अभिनय न कर पाए, तो छोटा-सा संवाद वापस लेने के लिए मोड़ ढूंढना पड़ता है। इससे मानसिक रूप से परेशानी होती है, भूख उड़ जाती है और आत्मा तड़पती है, फिर भी स्थिति ठीक होने का अभिनय लगातार करते रहना होता है। सही मोड़ काटना सीखते रहना होता है।

दिग्गज व्यक्ति अनुभव के वस्त्र बदल-बदल कर, अभिनय करते-करते निर्देशक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी नए मोड़ चुनने पड़ते हैं। शतरंज की बिसात पर नए मोहरे चलाना सीखना पड़ता है। कई मोड़ ऐसे भी आते हैं, जहां सार्वजनिक खेद प्रकट करना होता है। देखा जाए तो अपनी गलती पर अगर सचमुच अफसोस नहीं है, तो खेद प्रकट करना भी कई बार सही अवसर पर किया गया कुशल अभिनय होता है। जिंदगी में हर तरह का किरदार निभाना होता है जो उसी तरह के अभिनय की मांग करता है। यहां करतब भी जरूरी होते हैं। स्थिति के अनुसार एक दूसरे को स्थिर या अस्थिर करने के लिए विश्वसनीय करतब करवाए जाते हैं और कई बार तो असली मारधाड़ भी जरूरी हो जाती है, जो करनी ही पड़ती है। यह जिंदगी का खतरनाक मोड़ होता है, जिस पर आमतौर पर सभी ठहरना नहीं चाहते। ऐसी जगह रुकना एक तरह की मजबूरी होती है। पीड़ित व्यक्ति अगर शांत रहे तो बेहतर, नहीं तो फिर अनुभवी मोड़ चुनना होता है।

यह मोड़ होता है 'माफी मोड़', जहां अपनी गलती का अहसास करते हुए या फिर स्थिति को सामान्य करने के मकसद से माफी मांग ली जाती है। यह तारीफ के काबिल मोड़ होता है। सभी समझदार लोग इसकी तारीफ ही करते हैं। देखा जाए तो इससे दोनों काम हो जाते हैं। गुस्सा भी जाहिर कर दिया और माफी मांगकर स्थिति भी नियंत्रण में कर ली । माफी मांगते हुए अगर यह कह दिया जाए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या मेरे कहने का वह मतलब नहीं था तो भी तारीफ मिल सकती है। निजी जिंदगी में आराम से काटे गए मोड़ काफी राहत पहुंचाते हैं। अगर पत्नी और पति एक दूसरे को ऐसा कहते रहें तो अच्छा संवेदनशील व्यवहार माना जाता है, जिसमें रास्ते पर आगे जाकर मुड़कर लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। विकास के कारण बढ़ती आजादी ने हर एक को कुछ भी बोलने, देखने और करने का अधिकार दे दिया है, लेकिन आजादी के इस मोड़ पर कर्तव्य भुलाए जा रहे हैं। ड्राइविंग चाहे राजनीतिक, धार्मिक या पारिवारिक हो, ऐसी होनी चाहिए कि नियंत्रण बरकरार रहे। स्थितियों की आवाजाही उचित गति से चलती रहे। जहां मुड़ना है, उस जगह को भूला न जाए, ताकि आगे जाकर वापस आना न पड़े।

बच्चे तो बच्चे अभिभावकों को भी लगी मोबाइल की लत

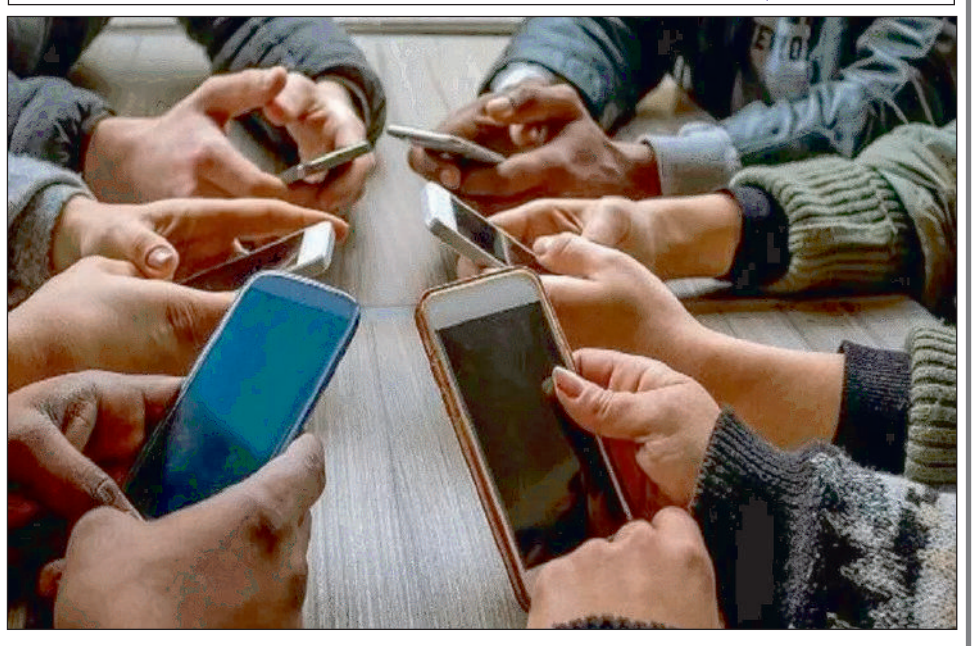

बच्चे तो बच्चे अभिभावकों को भी मोबाइल फोन की लत लग चुकी है। माता-पिता और बच्चों का मजबूत रिश्ता बनाने में स्मार्टफोन बाधक बन रहा है। देश के 76 प्रतिशत बच्चे तो 84 प्रतिशत अभिभावक एक-दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं. लेकिन स्मार्टफोन और इंटरनेट मीडिया उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। तभी 94 प्रतिशत बच्चे चाहते हैं कि उनके माता-पिता के स्मार्टफोन में कालिंग, मैसेजिंग और कैमरा जैसे सिर्फ तीन फीचर होने चाहिए। बच्चे नहीं चाहते हैं कि माता-पिता के स्मार्टफोन में इंटरनेट मीडिया, एंटरटेनमेंट और गेमिंग एप की सुविधा हो। दूसरी तरफ 75 प्रतिशत अभिभावक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके बच्चे स्मार्टफोन की लत की वजह से परिवार के साथ सार्थक रिश्ते नहीं बना पा रहे हैं। परंतु बच्चे और अभिभावक दोनों ही स्मार्टफोन की आदत छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो और साइबर मीडिया रिसर्च की तरफ से अभिभावक बच्चों के रिश्तों पर स्मार्टफोन का असर संबंधी अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। वीवो स्विच आफ 2024' सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि अभिभावक रोजाना औसतन पांच घंटे से अधिक तो बच्चे चार घंटे स्मार्टफोन पर अपना समय व्यतीत करते हैं। दोनों अपना अधिकतर समय इंटरनेट मीडिया और एंटरटेनमेंट एप पर बिताते हैं। 76 प्रतिशत अभिभावक और 71 प्रतिशत बच्चों ने सर्वे के दौरान यह माना कि वे स्मार्टफोन के बगैर नहीं रह सकते हैं। 64 प्रतिशत बच्चे मानते हैं कि उन्हें स्मार्टफोन की बुरी लत लग चुकी है। 60 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने बताया कि अगर उनके दोस्त इंटरनेट मीडिया एप से हट जाएं तो वे भी इसका उपयोग छोड़ सकते हैं। तीन में एक बच्चे ने तो यहां तक कहा कि इंटरनेट मीडिया एप का आविष्कार ही नहीं होना चाहिए था। वीवो इंडिया के कारपोरेट स्ट्रैटजी हेड गीतज चन्नना कहते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल सकारात्मक बदलाव और जिंदगी को आसान बनाने के लिए होना चाहिए। लेकिन स्मार्टफोन वास्तविक जीवन के रिश्तों में रुकावट बन सकता है। सर्वे से यह सवाल उठने लगा है कि स्मार्टफोन की इस दुनिया में परिवार कैसे सार्थक रिश्ते कायम हो सकता है। बच्चों में स्मार्टफोन की बुरी लत को देखते आस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

अब विदेश से जमकर आएगा पैसा ! भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमा पर बढ़ाई ब्याज दर

परिवहन विशेष न्यूज

आरबीआई ने बैंकों को अब एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष से कम अवधि की एफसीएनआर (बी) जमाएं अल्पकालिक वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) जमा चार प्रतिशत दर पर जुटाने की अनुमति दे दी है जबकि पहले यह 2 .50 प्रतिशत थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि भारत के पास अपने व्यापार को डी-डॉलराइज (de-dollarization) करने की कोई योजना नहीं है।

नई दिल्ली। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमाओं पर ब्याज दर सीमा बढ़ाने का एलान किया है। इस कदम का उद्देश्य रुपये पर दबाव के बीच पूंजी प्रवाह को बढ़ाना है। केंद्रीय बैंक ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है।

शुक्रवार से बैंकों को अब एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष से कम अवधि की एफसीएनआर (बी) जमाएं अल्पकालिक वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) जमा चार प्रतिशत दर पर जुटाने की अनुमति दे दी है, जबकि पहले यह 2.50 प्रतिशत थी।

इसी तरह, तीन से पांच वर्ष की अवधि की परिपक्वता अवधि वाली जमाओं पर एआरआर प्लस पांच प्रतिशत ब्याज दिया जा सकता है, जबकि पहले यह सीमा 3.50 प्रतिशत थी। एफसीएनआर पर यह छूट अगले वर्ष 31 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगी।

'म्यूलहंटर एआई' से बैंकों की जुड़ने की सलाह

आरबीआई ने शुक्रवार को बैंकों से कहा कि वे उसकी पहल 'म्यूलहंटर डाट एआइ' के साथ सहयोग करें, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल खातों (फर्जी खातों) को हटाया जा सके। म्यूल खाता एक बैंक खाता है, जिसका इस्तेमाल अपराधी अवैध तरीके से पैसा लूटने के लिए करते हैं।

गुमनाम व्यक्ति इन खातों को खोलकर इसमें लोगों से ठगी के पैसे जमा कराते हैं। इन खातों से धन हस्तांतरण का पता लगाना और उसे वापस पाना मुश्किल होता है।

डी-डॉलरीकरण को योजना नहीं: दास

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि भारत के पास अपने व्यापार को 'डी-डॉलराइज' (de-dollarization) करने की कोई योजना नहीं है। इसका मतलब है कि भारत दूसरे साथ के साथ व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल घटाने की दिशा में नहीं बढ़ रहा है।

आरबीआई गवर्नर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने का विकल्प चुनते हैं तो उन पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा ब्रिक्स मुद्रा के बारे में दास ने कहा कि यह समूह के सदस्यों द्वारा दिया गया एक विचार है, लेकिन इस पर कुछ चर्चाओं के अलावा कोई प्रगति नहीं हुई है।

दास ने कहा कि भारत का प्रयास वोस्ट्रो खातों की अनुमति देने और स्थानीय मुद्रा में व्यापार लेनदेन निपटाने के लिए दो देशों के साथ समझौते करने तक सीमित हैं। यह मूलरूप से हमारे व्यापार को जोखिम मुक्त करने के लिए है। एक मुद्रा पर निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है। उन्होंने कहा, 'डी-डॉलरीकरण हमारा उद्देश्य नहीं है और यह बिल्कुल भी विचाराधीन नहीं है।'

इस साल या अगले साल! कब आएगी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त? क्या कहता है नियम

परिवहन विशेष न्यूज

पीएम किसान योजना 19वीं किस्त केंद्र सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना में किसानों को किस्तों में सरकार की तरफ से राशि मिलती है। अभी तक किसानों के अकाउंट में योजना की 18वीं किस्त आ गई है। अब किसान 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि किसानों के अकाउंट में 19वीं किस्त कब आएगी।

नई दिल्ली। भारत सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद करने और एग्रीकल्चर सेक्टर को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) शुरू की थी। इस स्कीम में सरकार योजना के लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि देती है।

सरकार ने किसानों को अभी तक 18वीं किस्त दे दी है। अब करोड़ों किसान 19वीं किस्त (PM Kisan Yojana 19th Installment) का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि अकाउंट में 19वीं किस्त की राशि कब आएगी।

कब जारी होगी 19वीं किस्त

सरकार हर साल में योजना के तहत 6,000 रुपये राशि देते हैं। यह राशि किसानों को किस्त में मिलती है। हर किस्त में किसान के अकाउंट में 2,000 रुपये राशि आता है। यह राशि साल में 3 बार जारी होती है। सरकार 4-4 महीने के गैप में यह राशि डालती है।

चालू वित्त वर्ष में सरकार ने 2 किस्त जारी कर दिया है। अब इस कारोबारी साल की आखिरी किस्त आने वाली है। किसानों के अकाउंट में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को आई थी। अब माना जा रहा है कि किसानों के जनवरी-फरवरी में राशि आएगी।

ई-केवाईसी जरूरी

पीएम किसान का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। जो किसान ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं उन्हें योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। अगर आप भी योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवाना चाहिए।

ई-केवाईसी का प्रोसेस काफी आसान है। किसान पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट से यह प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। ई-केवाईसी के साथ किसानों को जमीन का सत्यापन भी करवाना होगा। इसके लिए किसान को जमीन के डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। इसके बाद अधिकारी द्वारा फिजिकल तौर पर जमीन का वेरिफिकेशन होगा।

क्या है ई-केवाईसी का प्रोसेस (E-Kyc Process)

स्टेप 1: पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाएं।

स्टेप 2: अब स्क्रीन पर e-KYC के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: अब आपको आधार नंबर भरना होगा।

स्टेप 4: आधार नंबर भरने के बाद गेट ओटीपी को सेलेक्ट करें।

स्टेप 5: इसके बाद रजिस्टर्ड फोन नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।

स्टेप 6: ओटीपी सबमिट करने के बाद ई-केवाईसी का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

धीमी विकास दर पर सीतारमण का जवाब,तीसरी तिमाही में पटरी पर आ जाएगी ग्रोथ रेट

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर 2024 में देश की आर्थिक विकास दर की रफ्तार सुस्त हो कर 5 .4 फीसदी निश्चित तौर पर दर्ज की गई है लेकिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास दोनों यह मानते हैं कि तीसरी तिमाही के बाद ग्रोथ रेट रफ्तार पकड़ लेगी। पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर, 2024 में देश की आर्थिक विकास दर की रफ्तार सुस्त हो कर 5.4 फीसदी निश्चित तौर पर दर्ज की गई है लेकिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास दोनों यह मानते हैं कि तीसरी तिमाही के बाद ग्रोथ रेट रफ्तार पकड़ लेगी।

निर्मला सीतारमण यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए विकास दर में दर्ज सुस्ती पर अपनी बात कह रही थी। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही की गिरावट को क्रमिक मानने से इनकार किया है। इस गिरावट की भरपाई तीसरी तिमाही में होने की उम्मीद जताते हुए सीतारमण ने कहा है कि दूसरी तिमाही में सार्वजनिक व्यय में कमी होने, पूंजीगत खर्चे के नहीं होने जैसे कुछ कारणों से विकास दर कम हुई है। मुझे उम्मीद है कि तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2024) में इस सभी की भरपाई हो जाएगी।

सीतारमण के इस बयान से कुछ ही घंटे पहले आरबीआई गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए सालाना आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7.2 फीसदी से घटा कर 6.6 फीसदी कर दिया। हालांकि उन्होंने भी यह स्वीकार किया की तीसरी तिमाही में विकास की रफ्तार तेज होगी।

डॉ. दास ने कहा कि जो भी संकेतक हैं वह बताते हैं कि दूसरी तिमाही में जो गिरावट हुई है वह अब और नीचे नहीं जाने वाली। अब इसमें सुधार के साफ संकेत है। कृषि सेक्टर और औद्योगिक गतिविधियों की स्थिति पिछली तिमाही (जुलाई-सितंबर) से बेहतर है।

ग्रामीण खपत में तेजी है, सरकार की खपत भी बढ़ रही है, निवेश में भी सुधार के लक्षण हैं। निर्यात में हमने 17.2 फीसदी की तेजी देखी है। सर्विस सेक्टर का निर्यात भी 22.3 फीसदी से बढ़ा है। ऐसे में तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 6.9 फीसदी और चौथी तिमाही में 7.2 फीसदी है।

नारायणमूर्ति ने खरीदा 50 करोड़ रुपये का आलीशान फ्लैट, लोकेशन का विजय माल्या से कनेक्शन

परिवहन विशेष न्यूज

इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति (Infosys founder Narayana Murthy) ने बेंगलुरु के किंगफिशर टावर्स (Kingfisher Towers) में 50 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट खरीदा है। चार साल पहले नारायण मूर्ति ने इसी टावर में 23वीं मंजिल में अपार्टमेंट खरीदा था। आपको बता दें कि प्रेस्टीज ग्रुप और माल्या की कंपनी के बीच एक जेवी के बाद इस टावर का निर्माण हुआ था।...

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस (Infosys) के फाउंडर को लेकर अब नया अपडेट आया है। न्यूज एजेंसी के अनुसार इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति (Infosys founder Narayana Murthy) ने बेंगलुरु के किंगफिशर टावर्स (Kingfisher Towers) में अपार्टमेंट खरीदा है। यह अपार्टमेंट की कीमक 50 करोड़ रुपये है। नारायण मूर्ति ने किंगफिशर टावर्स का 16वीं मंजिल पर स्थित अपार्टमेंट खरीदा है।

लग्जरी से भरा है ये अपार्टमेंट

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अपार्टमेंट 8,400 वर्ग फुट में फैला है। इस अपार्टमेंट में चार बेडरूम और पांच कार पार्किंग हैं। माना जा रहा है कि इस अपार्टमेंट की डील 59,500 रुपये प्रति वर्ग फुट पर हुई है। चार साल पहले भी नारायण मूर्ति ने इसी टावर की 23वीं मंजिल खरीदी थी। उस समय इस फ्लैट की कीमत 29 करोड़ रुपये थी।

क्या है किंगफिशर टावर

किंगफिशर टावर्स में 34 मंजिल है। यह मंजिल पूरी तरह से लग्जरी से भरा है। इस टावर में टोटल 81 अपार्टमेंट है। यह पूरा टावर 4.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस टावर की खास बात है कि यह टावर जहां पर है वहां पहले विजय माल्या का पैतृक घर था।

वर्ष 2010 में प्रेस्टीज ग्रुप और माल्या की कंपनी के बीच एक जेवी हुआ था। इस जेवी के तहत किंगफिशर टावर्स का निर्माण हुआ था। प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद इस टावर के लग्जरी अपार्टमेंट को 22,000 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बेचा गया था।

कई हस्तियों का है घर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किंगफिशर टावर्स में कई बड़ी हस्तियों के अपार्टमेंट हैं। इस टावर में बायोकॉन की किरण मजूमदार-शॉ का भी अपार्टमेंट है। वर्ष 2022 में कर्नाटक के मंत्री केजे जॉर्ज के बेटे राणा जॉर्ज ने भी इस टावर में अपार्टमेंट खरीदा था।

माना जाता है कि इस टावर में प्रत्येक अपार्टमेंट के निवासी हर तिमाही 5 लाख रुपये का मेंटेनेंस फीस देते हैं।

कितनी भी हो सैलरी, ऐसे बनाएं बजट- कभी कम नहीं पड़ेंगे पैसे

परिवहन विशेष न्यूज

50-30-20 Formula जॉब के साथ सेविंग करना बहुत जरूरी है। ऐसे में सेविंग और खर्चों को मैनेज करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक सही बजट बनाना काफी जरूरी है। इसके लिए फाइनेंशियल 50-30-20 फॉर्मूला काफी कारगार साबित होता है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि 50-30-20 फॉर्मूला क्या है और यह कैसे काम करता हैं। पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली। हम जॉब करते हैं तो साथ में जिम्मेदारी भी आती है। हम कोशिश करते हैं कि अपने माता-पिता को कोई आर्थिक मदद करें। इसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन, इसके लिए सही प्लानिंग होना जरूरी है। प्लानिंग के साथ बजट और अनुशासन का भी अहम रोल है।

हम आपको आप फाइनेंशियल सशक्त होने और सही बजट तैयार करने में मदद करेंगे। वैसे तो वित्तीय तौर पर बजट बनाने के लिए कई फॉर्मूला है, लेकिन इन फॉर्मूला में सबसे पॉपुलर 50-30-20 फॉर्मूला (50-30-20 Formula) है।

क्या है 50-30-20 फॉर्मूला ?(What is 50-30-20 Formula ?)

इस फॉर्मूला में आप अपनी सैलरी को तीन भाग में बांटते हैं। फॉर्मूला में 50 फीसदी हिस्सा खर्च, 30 फीसदी जरूरत और 20 फीसदी सेविंग होता है। यह फॉर्मूला सेविंग के साथ एक्सपेंस को मैनेज करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह कई फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में भी हेल्प करता है।

कैसे काम करता है ये फॉर्मूला ? (How does the 50-30-20 Formula work ?)

28 वर्षीय पूजा दिल्ली के पीजी में रहती है। वह मासिक 50,000 रुपये कमाती है। इसमें से वह हर महीने 10,000 रुपये अपने माता-पिता को भेजती है। अब सवाल आता है कि वह इस फॉर्मला के मदद से अपने खर्चों और आवश्यकताओं के साथ सेविंग कैसे करेगी ?

पूजा हर महीने अपनी सैलरी से 10,000 रुपये माता-पिता को देती है। इसके बाद उसकी कुल सैलरी 40,000 रुपये होती है। 50-30-20 फॉर्मूला के हिसाब से पूजा को मासिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा यानी 20,000 रुपये खर्च में होंगे। इस खर्च में पीजी का किराया, खाना,बिजली बिल आदि शामिल हैं।

अब बाकी बचे 50 फीसदी सैलरी को दो भाग में बांटे। बची हुई सैलरी का 30 फीसदी हिस्सा यानी 12,000 रुपये का इस्तेमाल जरूरत के लिए करें। जरूरत से हमारा मतलब लाइफस्टाइल से है जैसे जिम या कोई वर्कशॉप आदि पर खर्च करें। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप इन आवश्यकता में से भी कुछ राशि अवश्य बचाएं जो आपके छोटे गोल जैसे ट्रैवल ट्रिप या किसी महंगे ब्रांड के क्लोथ और स्मार्टफोन आदि को पूरा करने में मदद करें।

अब बाकी बचे 20 फीसदी यानी 8,000 रुपये को सेव करें। अपनी सेविंग और निवेश के साथ आपको हर महीने कुछ राशि इमरजेंसी फंड (Emergency Fund) में डालना चाहिए जो आपात स्थिति में आपको वित्तीय मदद करें। इसके अलावा आपको कुछ राशि को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको रिटर्न मिले जो आपकी सेविंग को बढ़ाने में मदद करें। हालांकि, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके सेविंग अकाउंट में हमेशा बैलेंस रहे जो मेडिकल इमरजेंसी में मदद करें।

इस तरह आप 50-30-20 फॉर्मूला की मदद से अपने खर्चों और जरूरतों के साथ सेविंग कर पाएंगे।

क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के बढ़ रहे मामले, बचने के लिए हमेशा रहे सतर्क

परिवहन विशेष न्यूज

Credit Card Fraud आज के समय में क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड की संख्या में तेजी देखने को मिली है। ऐसे में हमेशा फ्रॉड से बचने के लिए अपने कार्ड की डिटेल्स किसी को न दें। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचने के लिए कौन-सी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं।

नई दिल्ली। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब पेमेंट आसानी हो गया है। अब कैश न होने के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ने पेमेंट आसान किया है, लेकिन कई फ्रॉड भी हो रहे हैं। ऐसे में हमेशा सलाह दिया जाता है कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी कभी किसी को न दें।

अगर कभी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्रॉड हो जाता है तो आपको सबसे पहले कार्ड को ब्लॉक करना चाहिए। हाल ही में एक मामला सामने आया जिसमें कार्ड के ब्लॉक होने के बाद भी कार्ड यूजर के साथ फ्रॉड हुआ। अब सवाल आता है कि क्या कार्ड के ब्लॉक होने के बाद भी फ्रॉड हो सकता है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप कैसे इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं।

कभी न शेयर करें ये जानकारी

फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) और एक्सपायरी डेट किसी को शेयर न करें। अगर आप यह डिटेल्स शेयर करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है।

इसके अलावा आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमेशा इंटरनेशनल गेटवे से ऑनलाइन पेमेंट करें। इसमें आपको ओटीपी के माध्यम से पेमेंट करने की आवश्कता नहीं होती है। इसमें आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते समय कार्ड डिटेल्स देनी होगी।

क्या ब्लॉक कार्ड से भी हो सकता है फ्रॉड

किसी भी फ्रॉड होने पर आपको कार्ड को ब्लॉक करने की सलाह दिया जाता है। लेकिन, उत्तर प्रदेश के एक मामले में कार्ड के ब्लॉक होने के बाद भी ठगबाज ने कार्ड का इस्तेमाल किया। दरअसल, इस मामले में पता चला कि कार्ड ब्लॉक हुआ ही नहीं था। ऐसे में अगर आप भी कार्ड ब्लॉक करने जाते हैं तो आपको एक बार कन्फर्म कर लेना चाहिए कि कार्ड ब्लॉक हुआ है या नहीं।

क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होने पर क्या करें ?

अगर आपके साथ भी कभी कोई फ्रॉड होता है तो आपको जल्द से जल्द शिकायत करना चाहिए। आपको पुलिस के साइबर सेल से संपर्क करना चाहिए ताकि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए और पुलिस जांच शुरू करें।

भारतीय कृषि के भविष्य को आकार देने की आवश्यकता

(निमिषा सिंह-विनायक फीचर्स)

आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पाँच सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में सम्मिलित है। विश्व के सफलतम अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शामिल है। अन्य क्षेत्रों में भी भारत नियमित रूप से विकास की नई बुलंदियां छू रहा है बावजूद इसके भारत में एक क्षेत्र ऐसा भी है जो आज भी विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गया है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र आज भी उस स्थिति में नहीं पहुँच पाया है जिसे संतोषजनक माना जा सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि कृषि पर निर्भर देश के करोड़ों लोग आज भी बेहद अभावों में जीवन जीने को विवश हैं और कई बार ये कृषि के माध्यम से अपनी बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाते हैं।

किसान समुदाय को सशक्त बनाने नवाचारों का अन्वेषण और भारतीय कृषि के भविष्य को आकार देने के लिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर एंड कॉमर्स में दो दिवसीय राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से व्यावहारिक चर्चा करने के लिए देश भर से किसान नेता, कृषि वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रगतिशील किसान एक मंच पर एकत्रित हुए। सिफा के संस्थापक और मुख्य सलाहकार पी. चेंगल रेड्डी के अनुसार भारत में खाद्य सुरक्षा और इस क्षेत्र में वैश्विक निर्यातक बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के अवसर हैं। आज जलवायु परिवर्तन को ध्यान रखकर खेती करने और युवा प्रतिभाओं को खेती की ओर आकर्षित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्रों में भी अपार अवसरों की उपलब्धता है ,जिन्हें सही ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

भारतीय किसान संघ परिसंघ के मौजूदा चेयरमैन रघुनाथ दादा पाटील ने देश भर से आए किसान नेताओं और प्रतिनिधियों से कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसकी जीवनरेखा हैं। किसान सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। किसानों और वैज्ञानिकों के बीच अंतर को पाटने के लिए 'प्रयोगशाला को भूमि' से जोड़ने के प्रयासों की भी महती आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अत्याधुनिक अनुसंधान जमीनी स्तर तक पहुंचे। कृषि में विविधता लाने के लिए किसानों को गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलों के साथ-साथ मछली पालन, मधुमक्खी पालन और हाइड्रोपोनिक्स जैसे विकल्पों को भी अपनाना चाहिए ।सम्मेलन में न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत सतत कृषि के लिए नीतिगत पहल और योजनाओं, निर्यात नीति पर विस्तृत चर्चा की गई। पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक बालियान ने कहा कि भारत सरकार ने 2018 में एसेंसिल कमोडिटी एक्ट की पावर को एक्सरसाइज करते हुए चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तय किया था। ठीक उसी तरह केंद्र सरकार 23 फसलों पर भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के पावर को एक्सरसाइज करते हुए न्यूनतम बिक्री मूल्य तय कर सकती है ताकि इससे नीचे सौदे न हो सके। साथ ही आवश्यक है कि यह पूरे देश में लागू हो तभी यह कारगर हो सकेगा। बिहार की निमिषा सिंह ने राज्य में मंडी व्यवस्था को पुनः बहाल कराए जाने की बात कही। झारखंड की सुष्मिता सोरेन ने जल संकट पर चिंता जताई। जमीन होने के बावजूद जल की कमी की वजह से वहां खेती नहीं हो पा रही है। फसल बीमा का फायदा भी झारखंड के किसानों को ढंग से नहीं मिल पा रहा है। कृषि में सोलर ऊर्जा की भूमिका, पशुओं से फसल को होने वाले नुकसान और फसल बीमा जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई ।सिफा की बैठक में ह्यूमेन फाउंडेशन फॉर पीपल एंड एनिमल्स (HFPA) जिनमें श्री मार्कस कैम्पोस और श्री राजगोपाल रेड्डी भी शामिल थे। उन्होंने किसानों को उनके संवैधानिक अधिकारों और उनकी रक्षा के लिए सरकार के कानूनी आदेश के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुच्छेद 21 आवश्यकता पड़ने पर वन्यजीवों से नागरिकों के जीवन और आजीविका के अधिकार की रक्षा करता है। जंगली सूअर, नीलगाय आदि जैसे फसल पर हमला करने वाले जानवरों के लिए मुख्य वन्यजीव अधिकारी अपनी शक्तियों को सरपंच को सौंप सकता है, जो तब पंजीकृत शूटरों को एक निश्चित समय अवधि के भीतर जानवरों को मारने के लिए बुला सकता है। किसान सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सोलर ऊर्जा विशेषज्ञ गणधम श्रीनिवास राव ने बताया कि किस प्रकार उनके और उनके सहकर्मी वेणुगोपाल और पी. चेंगल रेड्डी के अनुरोधों, अभ्यावेदनों और लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। टावर बेस एरिया को भूमि मूल्य का 200 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। टावर के चार ग्राउंड-लेवल लेग और प्रत्येक तरफ एक अतिरिक्त मीटर विस्तार से घिरा स्थान टावर बेस एरिया के रूप में जाना जाता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर को मुआवजे के लिए अंतिम अधिकार दिया जाएगा। मुआवजे पर निर्णय लेने से पहले, हम अनुरोध करेंगे कि जिला कलेक्टर नवीनतम (14 जून 2024 को बिजली मंत्रालय के दिशा-निर्देश) दिशा-निर्देशों पर विचार करें।

दूसरे दिन के अंतिम सत्र में सिफा के मुख्य सलाहकार पी. चेंगल रेड्डी के मार्गदर्शन में सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सिफा की नई संगठन कार्यकारी समिति और प्रशासनिक टीम का गठन किया गया। महाराष्ट्र से रघुनाथ दादा पाटील को चेयरमैन और गुजरात के विपिन चंद्र पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई वहीं झारखंड दुमका से ताल्लुक रखने वाली सुष्मिता सोरेन,उत्तर प्रदेश से अशोक बालियान और तेलंगाना से मारा गंगा रेड्डी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद भार सौंपा गया। राष्ट्रीय किसान सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक से शंकर नारायण रेड्डी, गुजरात से बिपिन भाई पटेल, तमिलनाडु से आर व्ही गिरी, आंध्र प्रदेश से कोटी रेड्डी नरेंद्र बाबू, तेलंगाना से गोपाळ रेड्डी, निमू वसंता, माधव रेड्डी, सोमशेखर राव, उत्तर प्रदेश से अशोक बालियान, धर्मेंद्र मलिक, झारखंड से सुस्मिता सोरेन, बिहार से निमिषा सिंह, पंजाब से दलजीत कौर, तमिलनाडु से गुरूसामी धरमार, दिल्ली से कोटी रेड्डी, हरियाणा से सेवा सिंग आर्य, छत्तीसगढ़ से पारसनाथ साहू, कर्नाटक से बी.एम.हंसी, उड़ीसा से समीर साहू, महाराष्ट्र से शिवाजी नांदखिले के अलावा देश भर से आए किसान नेताओं ने कई विशेष मुद्दे जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कृषि उपज न बिके, इसका प्रावधान करना, मुख्य फसलों, मुख्य फल-सब्जी, दूध व शहद आदि को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में लाने, जल प्रबंध, कृषि सुधार, बाजार हस्तक्षेप योजना को प्रभावी बनाने, औसत बाजार भाव और लक्षित भाव के बीच जो अंतर हो, उस राशि यानि बाजार में हानि का भुगतान (मार्केट लॉस पेमेंट) किसानों को डीबीडी के माध्यम से किया जाए व कृषि को संविधान की समवर्ती सूची में रखने, कृषि को उद्योग का दर्जा देने के मामलों पर चर्चा की ।अब इन सभी मांगों के साथ एक ज्ञापन कृषि मंत्रालय को सौंपा जाएगा।

राष्ट्रपति ने 3 रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेस्वर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने जन्मस्थान पर हैं। द्रौपदी मुर्मू ने आज मयूरभंज के लोगों को रेलवे परियोजना की सौगात दी। इसके अलावा राष्ट्रपति ने बांगिरीपोशी के मिनी स्टेडियम में 3 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये 3 रेलवे परियोजनाएं हैं बुडामरा-चाकुलीआ, बांगिरिपोशी-गोरोमाहिसानी और बादामपहाड़-केओझर् ।जिले के लोगों को उम्मीद है कि इस रेलवे कनेक्शन से व्यापार, पर्यटन और वित्तीय क्षेत्र में विकास होगा। इसके लिए मयूरभंज के लोगों ने राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार बांगिरीपोशी आईं, इसलिए लोगों में काफी खुशी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 5 दिवसीय ओडिशा यात्रा का आज आखिरी दिन है। महामहिम ने आज रायरंगपुर में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति सबसे पहले बंगरीपोशी रेलवे स्टेशन के सभा स्थल पर पहुंचे. वहां उन्होंने बंगरीपोशी-गोरुमहिसानी, बुशमारा-चाकुवाले, बादामपहाड़-केंदुझार रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अलावा, वर्चुअल मोड में रायरंगपुर में जनजातीय अनुसंधान केंद्र, रायरंगपुर दंडबोश हवाई अड्डे के उन्नयन और रायरंगपुर उप-विभागीय अस्पताल में एक नए भवन के निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम भी हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन माझी, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जोएल ओराम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कानपुर में गोली से छात्रा की मौत की वजह प्रेम प्रसंग से जुड़ी : हत्या की आशंका से जारी गहन जांच

- एक युवक से चल रहा था छात्रा का प्रेम प्रसंग जानकारी होने के बाद नाराज थे परिजन
- मौके से तमंचा – कारतूस भी बरामद

सुनील बाजपेई

कानपुर। इस महानगर में प्रेम प्रसंग के चलते हत्याओं और आत्महत्या का दौर लगातार जारी है ,जिसके क्रम में एक और छात्रा की संदिग्ध हालातों में गोली लगने से मृत्यु हो गई।

फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं। साथ ही पुलिस ने घर से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। मामले में छात्रा के माना पिता और भाई के बयान में विरोधाभास होने की वजह से घटना की वजह प्रेम प्रसंग से भी जुड़ी मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने घटना को आत्महत्या बताया है। 11वीं की इस छात्रा ने खुद अपने पेट पर फायर झोंका या किसी ने उसे गोली मारी, अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। यह घटना बिधनू के जामू गांव की है। यहां रहने वाले विनय सिंह चंदेल एक वकील के यहां मुंशी हैं। उनकी की बेटी श्रेया (16) की घर के अंदर ही संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। इस बारे में पुलिस ने ग्रामीणों से भी बात की। जिसमें सामने आया कि छात्रा की गांव के ही एक युवक से दोस्ती थी। उनका लव अफेयर खुलकर सामने आया, तब लड़की के पिता ने लड़के के परिवार पर दबाव बनाया। उनके बीच झगड़ा भी हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इसके बाद लड़के का परिवार औरैया शिफ्ट हो गया। करीब 4 महीने पहले परिवार फिर गांव लौटा था। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया। गांव के लोगों ने बताया कि अब एक बार फिर लड़का और लड़की मिलने लगे थे। इसके बाद पुलिस ने लड़की के परिजनों से अलग-अलग बातचीत की। जिसमें लड़की की मां ने बताया कि घर के बाहर दुकान में गोली लगी है। पिता का कहना है कि घर के अंदर गोली चली। जबकि भाई बार-बार अपना बयान बदलता रहा। यही वजह है कि पुलिस घटना को संदिग्ध में पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है।

बांग्लादेश के हिन्दुओं पर हिंसा, भारत सरकार को राजनैतिक और राजनयिक प्रयास तेज करने की जरूरत

(डॉ. चन्दर सोनाने-विनायक फीचर्स)

पिछले दिनों देशभर में बांग्लादेश में हिन्दूओं पर हो रही हिंसा और अत्याचार के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, बंद, रैली, सभा आदि का सफल आयोजन किया गया। जगह-जगह हो रहे इन प्रदर्शनों में सकल हिन्दू समाज की प्रमुख माँग यह रही कि भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाला जाए, ताकि वहाँ अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और धार्मिक स्वतंत्रता को कायम रखा जा सके। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को इन अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया जाए। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच कराई जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति न हो सके।

बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही वहाँ हिन्दूओं पर अत्याचारों की श्रृंखला शुरू हो गई थी, जो अब विकराल रूप ले चुकी है। देशभर में हो रहे प्रदर्शन यह बताने के लिए पर्याप्त है कि बांग्लादेश में हिन्दूओं पर हो रहे अत्याचारों पर तुरंत रोक लगे। समय की माँग भी यही है।

केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक बांग्लादेश में हिन्दूओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाना आश्चर्यजनक और दुखद है। केन्द्र सरकार द्वारा 5 अगस्त के बाद से पिछले चार माह के दौरान बांग्लादेश को सख्त कार्रवाई करने के संकेत दे देने चाहिए थे। किन्तु अभी तक यह नहीं हो सका है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह सब जानते है। युद्ध से किसी का भला नहीं होता। पिछले एक साल से अधिक समय से रूस और यूक्रेन में चल रहा युद्ध इसका ज्वलंत उदाहरण है।

केन्द्र सरकार को चाहिए था कि वह सबसे पहले विदेश मंत्री को बांग्लादेश भेजते और वहाँ की सरकार को बांग्लादेश में हिन्दूओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बारे में भारत की चिंता से अवगत कराते। किन्तु यह नहीं हुआ। इसके साथ ही देश के गृहमंत्री को बांग्लादेश के गृहमंत्री से चर्चा कर वहाँ हो रही हिंसा पर तुरंत नियंत्रण के प्रयासों के बारे में भी चर्चा करनी थी, किन्तु यह भी नहीं हो सका। यह दुखद और आश्चर्यजनक है।

प्रधानमंत्री जी को अब इस संबंध में राजनैतिक और राजनयिक प्रयासों को तेज करने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात करने की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही भारत के मित्र देश अमेरिका, रूस एवं अन्य देशों के प्रमुखों से भी चर्चा कर बांग्लादेश पर दबाव डालने की आवश्यकता है। आज इस सबकी बहुत जरूरत है।

जब बांग्लादेश पर चारों ओर से राजनयिक दबाव पड़ेंगे तो उसे हिन्दूओं की सुरक्षा के लिए न केवल बाध्य होना पड़ेगा, बल्कि उसे हिन्दूओं पर लगातार हो रहे अत्याचारों और हमलों पर नियंत्रण के प्रयास करने ही होंगे। कोई देश अलग-थलग नहीं रहना चाहता। मजबूरी में ही सही उसे वो सब करना जरूरी होगा, जो वह अभी तक नहीं कर रहा है।

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाएँ दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। यह पूरे देशवासियों के लिए चिंता की बात है। देश में कांग्रेस सहित प्रतिपक्ष के अन्य सभी राजनैतिक दलों की बांग्लादेश में हिन्दूओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी भी दुखद और आश्चर्यजनक है। प्रतिपक्ष को चाहिए था कि वे संसद में बांग्लादेश में हिन्दूओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार द्वारा कार्रवाई करने की मांग करें किन्तु यह भी नहीं हुआ।

आज समय की माँग है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिन्दूओं पर हो रहे अत्याचार पर सभी राजनैतिक और राजनयिक प्रयासों को तेज करें। इसमें उन्हें प्रतिपक्ष का भी सहयोग लेना चाहिए। जब पूरा देश एक स्वर में बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध मुखर आवाज बुलन्द करेगा तो बांग्लादेश को ठोस कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा।

(विनायक फीचर्स)

बांग्लादेश की धरती पर भारत के खिलाफ साजिशें

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जुलाई में हुए तख्तापलट के बाद से ही भारत विरोधी लहर चल रही है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भी चरम पर है। भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुल 20 से 22 टेरर कैंप खड़े किए गए हैं। ये सभी कैंप्स उन इलाकों में हैं, जहाँ से भारत में घुसपैठ के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते रहे हैं। भारतीय बॉर्डर के नज़दीक ही इन आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है।

-प्रियंका सौरभ

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा के खिलाफ वैश्विक स्तर पर चिंता की लहर बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन की संसद तक में यह मुद्दा उठ चुका है। अब अमेरिका में भी इसके खिलाफ राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के करीब बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। इसके बावजूद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों से लेकर चीन-पाकिस्तान तक के दबाव में अपना भारत विरोधी एजेंडा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब यूनुस सरकार ने एक और ऐसा क़दम उठाया है, जिससे भारत को बड़ा झटका लगने जा रहा है। यूनुस सरकार ने शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के साथ किए गए मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़े एक समझौते को रद्द कर दिया है। इस समझौते से भारत अपने नॉर्थईस्ट राज्यों में इंटरनेट की स्पीड और कवरज बढ़ाने की जुगत भिड़ा रहा था, लेकिन अब यह उम्मीद टूट गई है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों पर हमलों के बीच ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई एस आई बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थियों में से भारत के खिलाफ आतंकी तैयार करने में जुटी हुई है।

बांग्लादेश में हिंदुओं की एथेनिक क्लींजिंग चल रही है। 53 साल बाद पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार भेज रहा है। खालिदा ज़िया और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच मुलाकातें भी हो रही हैं। बांग्लादेश में वही हो रहा है जो पहले बाबर ने किया फिर कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ। दरअसल पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल करते हुए भारत को टारगेट कर रहा है। वह भी 3 तरफ़ से। पाकिस्तान का पहला शिकार बांग्लादेशी हिंदू, जिनपर इतने अत्याचार हो रहे है कि हर परिभाषा छोटी पड़ जाए. दूसरा हिस्सा है बांग्लादेशी फ़ौज को मदद, जिसके जरिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोलना चाहता है और तीसरा भारतीय सामानों का बहिष्कार...ताकि भारत को आर्थिक चोट पहुँचे। बांग्लादेश ने कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और त्रिपुरा (अगरतला) में अपने शीर्ष राजनयिकों को 'परामर्श' के लिए वापस बुलाया है। वहीं बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नोटों से भी हटा दी गई है।

भारत के नॉर्थ-ईस्ट इलाके के कई राज्यों में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। इसी कारण भारत ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के दौरान एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत बांग्लादेश का उपयोग रीजनल डिजिटल हब के तौर पर किया जाना था, जिसमें बांग्लादेशी सीमा पर इंटरनेट सर्किट स्थापित कर नॉर्थईस्ट राज्यों में डेटा ट्रांसमिशन के लिए 'बैंडविड्थ ट्रांजिट' सुविधा देनी थी। यह काम भारती एयरटेल को बांग्लादेशी कंपनियाँ समीट कम्युनिकेशंस और फाइबर एट होम के साथ मिलकर करना था। यह प्रस्ताव इन कंपनियों ने बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन के सामने पेश किया गया था, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी।

यूनुस सरकार ने अब इस समझौते की सैद्धांतिक मंजूरी ख़त्म कर दी है। इसे रद्द करने का आदेश जारी करते हुए इससे बांग्लादेश को कोई आर्थिक लाभ नहीं होने का तर्क दिया है। हालांकि यह फ़ैसला केवल भारत विरोधी नहीं है। दरअसल इस ट्रांजिट लिंक को तैयार करने के लिए एयरटेल के साथ जुड़ी कंपनी समीट कम्युनिकेशंस के चेयरमैन मोहम्मद फारिद खान का शेख हसीना की अवामी लीग से भी नाता है। वे अवामी लीग के सांसद फरीक खान के छोटे भाई हैं। यह भी यूनुस सरकार के फैसले का कारण माना जा रहा है।

बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक बार फिर इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने बताया कि ढाका के नमहट्टा स्थित इस्कॉन मंदिर में चरमपंथियों की भीड़ ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि नमहट्टा के मंदिर में शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात चरमपंथी मुस्लिमों ने हमला करने के बाद सारी मूर्तियों पर तेल छिड़ककर आग लगा दी है। पूरा मंदिर जला दिया गया है। ये मंदिर ढाका जिले के तुराग पुलिस थाने के अंतर्गत धौर गाँव में स्थित है। वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। इस्कॉन इन घटनाओं की जानकारी लगातार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को दे रहा है, लेकिन पुलिस-प्रशासन इन्हें नहीं रोक रहा है।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ अमेरिका में भी चिंता जताई गई है। भारतीय मूल के अमेरिकियों ने इसके खिलाफ वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब और शिकागो में अगले दो दिन के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करने का ऐलान किया है। यह प्रोटेस्ट मार्च हिंदू एक्शन संगठन की तरफ़ से व्हाइट हाउस के पास 'बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार' नाम से सोमवार को आयोजित होगा, जबकि रविवार को शिकागो में 'नरसंहार रोकें: बांग्लादेश में हिंदुओं की जान बचाएं' के नाम से किया जाएगा। इनमें अमेरिका के नामी-गिरामी भारतीय लीडर मौजूद रहेंगे।

बांग्लादेश की धरती पर कट्टरपंथियों के दबाव में फंसी मुहम्मद यूनुस सरकार ने अब पाकिस्तान को खुलकर मनमानी करने की छूट दे दी है। इससे वहाँ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी एक्टिव हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में पाकिस्तान रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकी बना रहा है। इन रोहिंग्या आतंकियों को भारत में हमले करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज से 53 साल पहले लाखों बांग्लादेशियों ने...पाकिस्तान के क्रूर शासन से आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी। लेकिन वह कुर्बानियाँ अब कब्र में दफ्न कर दी गई हैं...और बांग्लादेशी कट्टरपंथी पाकिस्तान को अपना रहनुमा मानने लगे हैं।

बांग्लादेशी चिल्ला-चिल्ला कर पाकिस्तान का नाम तो ले रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा इतिहास पढ़ा होता तो अफगानिस्तान नज़र आता, जहाँ पाकिस्तान ने दखल दी। तालिबान खड़ा किया और अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। अगर बांग्लादेश अब भी इस साज़िश को नहीं समझ पाया...तो शायद बांग्लादेश को दूसरा अफगानिस्तान कहा जाएगा।

हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में श्री हनुमान सेना द्वारा बांग्लादेश का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा

आगरा, पंकज जैन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एवं हिंसक हमलों के विरोध में श्री हनुमान सेना द्वारा आज कलक्ट्रेट परिसर में बांग्लादेश का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। श्री हनुमान सेना ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध किया कि हिन्दुओ पर हो रहे अत्याचार एवं हिंसक हमलों को तत्काल प्रभाव से बंद किए जायें और हिन्दूओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये। बांग्लादेश की कट्टरपंती सरकार के लिए श्री हनुमान सेना के सभी योद्धाओं में इतना रोष था कि बांग्लादेश के झंडे जलाये गये। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से, सतीश शिवाजी प्रदेश अध्यक्ष, ज्ञानेन्द्र फौजदार प्रदेश महामंत्री, लोकपाल चहार, जयदीप गोला, रामू चौधरी, पंकज कुंतल, देवराज, सौरभ प्रजापति, शिवम शर्मा, नरेश प्रजापति, राजू लवानिया, शिवम पाराशर, सोवियत, चंदर दिवाकर, अजीत चौधरी, व अमन चौधरी आदि उपस्थित रहे।

कटक रेलवे स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओशिा

कटक/ भुबनेश्वर : कटक रेलवे स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया जाएगा। इसका उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। रेलवे स्टेशन हवाई अड्डे का भ्रम पैदा कर रहा है। हवाई अड्डा एक रेलवे स्टेशन जैसा दिखता है। ब्रिटिश मूल के कटक रेलवे स्टेशन को आधुनिक व्यवस्था के साथ नया लुक मिला है। यह रेलवे स्टेशन राज्य का पहला स्टेशन है जो सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। दूसरे प्रवेश द्वार में टिकट काउंटर, ओएसओपी स्टॉल और अत्याधुनिक फूड कोर्ट के साथ एक पूरी तरह से लागू भवन परिसर है। इसमें पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं के साथ एक सुनियोजित क्षेत्र है। यात्रियों की सुचारू आवाजाही के लिए एस्केलेटर, सीढ़ियाँ, लिफ्ट प्रदान की जाती हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए चौड़ी बर्थ की भी व्यवस्था की गयी है। इसी तरह, बालेश्वर रेलवे स्टेशन पर एक फुट ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया जाएगा। रेलवे ट्रैक पार करने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक प्रावधान किया गया है। यह ओवरब्रिज प्लेटफार्म 1, 2, 3 और 4 को जोड़ेगा।

मौसम विभाग का अलर्ट: भारी बारिश और बर्फबारी से बढ़ सकती है मुश्किलें, घरों में रहने की सलाह

इशिका मुख्य रिपोर्टर न्यूज परिवहन विशेष

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों के लिए मौसम की गंभीर चेतावनी जारी की है। भारी बारिश, बर्फबारी, और कड़कड़ाती ठंड के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों से अपील की गई है कि वे अत्यावश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलें।

उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ा

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी होने की संभावना है। श्रीनगर में बीती रात का तापमान माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। शोपियां और गुलमर्ग जैसे इलाकों में भी कड़कड़ाती ठंड देखी जा रही है। इन इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। कोहरा और शीतलहर से इन क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होगा। यातायात और परिवहन सेवाएं बाधित हो सकती हैं।

स्कूल-कॉलेज बंद करने के आदेश

कुछ राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें।

यात्रा से पहले रहें सतर्क

पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। सड़कों पर बर्फ जमा होने और फिसलन के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।

सुरक्षा के उपाय अपनाएं

1. गर्म कपड़े पहनें और शरीर को ठंड से बचाएं।
2. घर से बाहर निकलने से पहले मौसम का हाल जानें।
3. कोहरे के कारण वाहन चलाते समय सतर्क रहें।

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम के और खराब होने की संभावना जताई है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023